www.tamsasanket.com
वर्षः 29 || अंक 144 || अम्बेडकरनगर
शुक्रवार
14 अगस्त 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:37
सूर्यास्तः 06:45
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 28°00

पेज 07

विशेष समाचार
विदेशी चंदे पर नियंत्रण और... >>पेज 04
तिरंगा यात्रा में 80 छात्राएं ... >>पेज 06
19 साल बाद आवारापन की ...

योगी सरकार की चुनाव से पहले 20 हजार, फिर 10-10 हजार की 3 किस्त देने की तैयारी

50 हजार रू महिलाओं को देने की योजना

योगी सरकार जेन-जी आंदोलन के बीच वोटबैंक को साधने के लिए महिला सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजना लाने की तैयारी में है। महिला कल्याण विभाग के जरिए योजना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है।

सहायता

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ । यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटबैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

चुनाव से पहले 20 हजार रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। सरकारी सूत्रों से दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक, योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी तक हो सकते हैं। दरअसल, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू की जाएगी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की थी। इसका उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना था।

>> (शेष पेज 06 पर)

बिहार की तरह यूपी में भी महिलाएं ही गेमचेंजर

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। एनडीए ने वहां 202 सीटें जीती थीं। एनडीए की उम्मीद से ज्यादा जीत में महिलाओं के अभूतपूर्व समर्थन और वोटों को आधार माना गया। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव का कारण चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना माना गया। प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं। इसीलिए मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी के बाद यूपी में भी महिलाओं और बेटियों के वोट को साधने के लिए भाजपा गेमचेंजर योजना लागू करने वाली है।

7.20 करोड़

गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता

सरकार योजना में एससी, एसटी परिवारों की महिलाओं के साथ बीपीएल परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देगी। इसमें ऐसे परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। सरकार के लोगों का मानना है कि महिलाओं को नकद प्रोत्साहन की योजना विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की योजना सबसे पहले मध्यप्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी।

>> (शेष पेज 06 पर)

महिला वोट की ताकत

- उत्तर प्रदेश 7.20 करोड़
- महाराष्ट्र 4.46 करोड़
- बिहार 3.41 करोड़
- मध्य प्रदेश 2.75 करोड़
- झारखंड 1.26 करोड़
- छत्तीसगढ़ 1.04 करोड़

सपा के पीडीए की काट बन सकती हैं महिलाएं

भाजपा नेता मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सहायता देना सपा के पीडीए की काट बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए का मुद्दा काम कर गया था। नतीजतन, भाजपा की सीटें 64 से घटकर 34 रह गई थीं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने खुद माना था कि अगर आज चुनाव हों, तो यूपी में भाजपा को 188 सीटें मिलेंगी।

50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी

हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत हुई थी। इसके बाद यूपी के सीएम योगी, भाजपा के लिए यूपी विधानसभा चुनाव- 2027 किसी चुनौती से कम नहीं है। बिहार में प्रचंड जीत के बाद दबाव यूपी में बढ़ गया है।

यूपी में 98 लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ीं

यूपी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। इसके तहत 10-10 महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी पर आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाती है। यूपी में इस समय 8,99,398 परिवारों की 98,76,389 महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं।

> राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं- भाजपा के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वह 5 वोट प्रभावित करती है। खासतौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके वोट तो संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय हो जाता है। यूपी में भी करीब 5 करोड़ 67 लाख महिला वोटर हैं।

पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला

नांदेड़ में निहंग ने कृपाण मारी, मोदी ने हाल पूछा

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

लुधियाना/महाराष्ट्र । महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक, गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला किया। बादल के हाथ में चोट लगी है।

हमले के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर हुई। पुलिस ने हमले के आरोपी निहंग जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुखबीर बादल परिवार के साथ नांदेड़ के गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। हमले के बाद उन्हें यशोसाईं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

- महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए
- डिप्टी सीएम ने सुरक्षा चूक मानी

>> (शेष पेज 06 पर)

यूपी में सपा सरकार बनी तो आजम खान बनेंगे गृहमंत्री

शिवपाल यादव ने रामपुर में किया ऐलान

घोषणा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और विधायक शिवपाल सिंह यादव बुधवार को जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने पहुंचे। शिवपाल ने करीबन एक घंटे उनसे जेल में मुलाकात की। बाहर आने के बाद शिवपाल ने मीडिया से कहा कि इस बार सपा सरकार में आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल ने आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम से मिले। इसके बाद शिवपाल जौहर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिले और उनके साथ बैठक में समस्या को सुना।

- मालिक पर झपटी बाघिन, भैंसों ने दौड़ाकर बचायी जान
- 'आजम खान के साथ हो रहा जुल्म'

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

झारखंड छात्र आंदोलन- 500 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर

रांची । झारखंड छात्र आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया था।

फैसला सुनवाई

डायन बताकर हत्या जैसी कुप्रथाएं रहीं तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायन बताकर महिलाओं की हत्या करने जैसी कुप्रथाएं जारी रहेंगी, तो देश में लोकतंत्र नहीं टिक सकता।

कोर्ट ने ओडिशा में 1998 में एक महिला की डायन बताकर हत्या करने के मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि इस मामले में महिला की बेटी ने अपनी मां को बेहद क्रूर तरीके से मारे जाते देखा था।

प्रियंका गांधी के गोमूत्र-एक्सपर्ट वाले बयान के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम

नई दिल्ली। IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को 'गोमूत्र एक्सपर्ट' बताने वाले प्रियंका गांधी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की गई है। इसे 13 अगस्त सुबह 9 बजे तक 14 हजार लोगों का समर्थन मिल चुका है।

देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा : राहुल

हमारा काम आवाज बुलंद करना

सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है। सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है।

दिल्ली में हो रहे कांग्रेस का 'रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ' के अधिवेशन में राहुल ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते थे। छात्र परेशान थे और अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सरकार को समझ आ गया है कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कोशिशें सरकार को परेशान कर सकती हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

पीएम मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की कूटनीति विदेशी नेताओं को गले लगाने से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह विचार कहां से आया। उन्हें लगता है कि गले लगाना ही विदेश नीति है। ऐसा कहते हुए राहुल ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगा लिया। वहीं, दीक्षित ने चुटकी लेते हुए कहा- आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था? >> (शेष पेज 06 पर)

काशी में घाट डूबे, अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार, 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 18 मजदूर फंसे

रेस्क्यू

- शिमला के गांव में धंस रही पहाड़ी, 100-150 घरों पर खतरा
- भारी बारिश में दिल्ली की सड़कें डूबीं
- स्कूल बस गड्ढे में फंसी, पलटने से बची

तमसा संकेत,एजेंसी

नई दिल्ली । उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच चमोली में एक टनल में अचानक पानी भर गया। टनल में काम कर रहे 18 मजदूर अंदर फंस गए। सात मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

उधर, उत्तर प्रदेश के बनारस में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया है। घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

> दिल्ली में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में जलभराव हो गया। मोटी बाग मेट्रो स्टेशन के पास की सड़कें भी पानी में डूब गईं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह-जगह लंबा जाम भी लग गया।

चमोली में टनल में अचानक पानी आया

चमोली में एचसीसी (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी) की एक टनल में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। पानी का तेज बहाव आने से 18 मजदूर फंस गए। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने सात मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

>> (शेष पेज 06 पर)

प्रदर्शन : लोकसभा 1 मिनट-राज्यसभा 1 घंटे चली, मोदी-शाह और राहुल सदन में मौजूद रहे

संसद सत्र खत्म

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिड़ला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

वहीं, राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया।

>> (शेष पेज 06 पर)

इधर, विपक्षी सांसद संसद के बाहर बंदर का खिलौना लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

राज्यसभा में 114 घंटे में से 76 घंटे 34 मिनट काम नहीं हुआ

मानसून सत्र में राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन राज्यसभा में लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ। यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई।

लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ

मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं, 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुईं। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था। 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं।

गुटखा-तंबाकू पर सरकार ने 1 साल के लिए लगाया बैन

खरीदना-बेचना और बनाना सब पर प्रतिबंध

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

कर्नाटक । अगर आप गुटखा-तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या इसके कारोबार से जुड़े हैं. तो यकीन मानें यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर एक साल की रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध सिर्फ बिक्री पर नहीं है. इसके साथ ही यह बैन बनाने में, स्टोर करने में, सामान को इधर से उधर भेजने-पहुंचाने में भी लागू रहेगा. जिसके बाद पूरे राज्य में जांच अभियान तेज कर दिया गया है. तो आइए बिना देर समझते हैं क्या है मामला. मामला कर्नाटक का है. राज्य के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे संबंधित उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, ले जाने-पहुंचाने, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।

- कर्नाटक में गुटखा-तंबाकू पर बड़ा फैसला
- सिर्फ दुकानदारों पर नहीं पड़ेगा असर

>> (शेष पेज 06 पर)

महिला ठग ने 1.40 करोड़ हड़पे, 7 दिन पहले करवाई थी एफआईआर रोते हुए मां-पिता पहुंचे

डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में 45 साल के डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। गुरुवार सुबह साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद डॉक्टर छत पर गए। करीब 15 मिनट तक टहले, फिर छत से छलांग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर डॉक्टर की पत्नी दौड़कर नीचे पहुंचीं। डॉक्टर खून से लथपथ पड़े थे।

आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को डॉक्टर की जेब से एक पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए महिला ठग गरिमा सिंह को जिम्मेदार बताया।

पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर से गरिमा सिंह ने 1.40 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके बाद से वह सदमे में थे। उन्होंने 7 दिन पहले गरिमा सिंह और उसके रेलवे अफसर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, उससे एक दिन पहले ही पुलिस ने गरिमा और उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना शहर के गोरखनाथ क्षेत्र की है। 5 अगस्त को पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने एम्स थाने में 1.40 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि महराजगंज के बरगदवां में डॉ. दिलीप कुमार सिंह पशु चिकित्साधिकारी के पद पर हैं। वह मेरे मित्र हैं। उन्हें पता था कि मैंने होम लोन लिया है। डॉ. दिलीप कुमार की गरिमा सिंह रिश्तेदार है। फरवरी- 2026 को गरिमा ने मुझे फोन किया। उसने मुझसे पूछा कि मेरा कोई लोन चल रहा है क्या? मैंने उसे बताया कि मेरा एक होम लोन चल रहा है। गरिमा ने कहा कि मैं अपने मित्र के साथ एक फाइनेंस फर्म में काम करती हूं। एक स्कीम है, जिसमें होम लोन क्लोज करा दिया जाता है।

पत्नी बोलीं- बैंक से लगातार फोन आ रहे थे, पति डिप्रेशन में थे

पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित बसंत इनक्लेव की दूसरी मंजिल पर रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉ. सुमित्रा सिंह, बेटा अरिहंत सिंह (12) और बेटी बिन्नी (7) हैं। डॉ. सुमित्रा ने बताया- मेरे पति ने बैंक से लोन लेकर महिला ठग गरिमा सिंह को पैसे दिए थे। बैंक से लगातार फोन आ रहे थे। इसके चलते वह डिप्रेशन में थे। वह कहते थे कि सवा लाख की सैलरी में 3 लाख रुपए की EMI होगी, तो क्या होगा? कैसे होगा? इतना बड़ा अमाउंट है, कैसे भरेंगे?

पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह (45) महराजगंज के नौतनवा में तैनात थे। उनकी पत्नी डॉ. सुमित्रा सिंह भी पशु चिकित्सक हैं। घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर के पिता पारस नाथ सिंह और मां कुंती सिंह मऊ से गोरखपुर पहुंचे। बेटे का शव देखकर दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।

यह वही बिल्डिंग है, जिससे कूदकर पशु चिकित्सक डॉ. परमात्मा सिंह ने सुसाइड किया। वह इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर परिवार के साथ रहते थे।

पहले काशी में शांति थी, अब भीड़:कथावाचक प्रदीप मिश्रा

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी । प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। बाबा विश्वनाथ को बेलपत्र अर्पित किए। इस दौरान सतुआ बाबा भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर के आर्चक श्रीकांत मिश्र ने प्रदीप मिश्रा को पूजन कराया।

बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रदीप मिश्रा ने भारत माता मंदिर के सामने लोगों को 'घर-घर तिरंगा' अभियान का संदेश दिया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। उन्होंने लोगों से देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

काशी में बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि काशी मूल रूप से शांति की नगरी है, लेकिन अब यहां का स्वरूप काफी बदल गया है। उन्होंने कहा कि काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं।

बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए,भारत माता मंदिर के सामने तिरंगा लेकर जयकारा लगाया

इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ती है, शोर होता है और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि पहले की काशी में इस तरह की भीड़ और जाम का नजारा कम देखने को मिलता था।

प्रदीप मिश्रा ने काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और उस पर हुए हमलों का भी जिक्र किया।

फास्ट न्यूज

हाईकोर्ट में बच्ची ने मां को पहचानने से इंकार किया

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची अनुष्का की कस्टडी उसके पिता सतेंद्र कुमार के पास बरकरार रखी है। कौशांबी के पश्चिम शरीरा थाने की पुलिस ने कोर्ट के 30 जुलाई 2026 के आदेश के तहत बच्ची को हाईकोर्ट में पेश किया था। बच्ची ने मां को पहचानने से इंकार कर दिया। इसके बाद फैसला पिता के पक्ष में आया।

कुत्ते ने बच्चे का सिर-चेहरा नोचा, 50 टांके लगे

वाराणसी । वाराणसी में गुरुवार सुबह 11 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने BHU कैंपस में बच्चे के सिर और चेहरे को दौड़ा-दौड़ाकर नोचा। इससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे को गंभीर हालत में BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 50 टांके लगाए हैं। डॉक्टरों ने परिवारवालों को बताया कि कुत्ते ने बच्चे को बहुत बुरी तरह से काटा है। बच्चे के पिता खुद BHU अस्पताल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने BHU प्रशासन को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग भी की है।

डिप्टी सीएम ने बांधी पगड़ी

प्रयागराज । स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बृहस्पतिवार को संगमनगरी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। भाजपा की ओर से सिविल लाइंस में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद यात्रा की अगुवाई की। तिरंगे से सजे रथनुमा वाहन में सबसे आगे खड़े होकर उन्होंने हाथ में तिरंगा लहराया। उनके साथ हजारों लोगों का हुजूम भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ता रहा।

उमर अहमद के काफिले से जुड़ी 2 लग्जरी कारें जब्त

टोल बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रतापगढ़ । प्रतापगढ़ पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले से जुड़ी दो लग्जरी कारें जब्त की हैं। हथिगवां पुलिस ने गुरुवार को यह कार्रवाई हथिगवां थाना क्षेत्र के अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा पर टोल बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को वाहन से कुचलने के प्रयास के आरोप में की।

दोनों स्कॉर्पियो-एन प्रयागराज से बरामद की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल लोगों की पहचान में जुटी है।

आरोप है कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे उमर अहमद के काफिले में शामिल कुछ वाहनों में सवार लोगों ने टोल शुल्क को लेकर कर्मचारियों से गाली-गलौज और दबंगई की। शिकायत के मुताबिक, कुछ वाहनों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और बिना शुल्क दिए निकल गए। टोल

कर्मचारियों ने वाहन से उन्हें कुचलने के प्रयास का भी आरोप लगाया। टोल प्लाजा के मैनेजर मो. इसहाक की शिकायत पर हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें हत्या के प्रयास, गाली-गलौज, धमकी और लापरवाही से वाहन चलाने समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मुकदमे में वाहन नंबर UP70GQ4834 और UP70GV2915 के अलावा अन्य अज्ञात वाहनों को भी शामिल किया गया है। पुलिस टीम ने गुरुवार को वाहनों की तलाश शुरू की। पहली स्कॉर्पियो-एन बरौंधा अंडरपास के पास परेवा नारायणपुर मोड़, लखनऊ-प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन से बरामद हुई।

एक की बहन से अफेयर था, दोस्त के साथ समझाने गया था, बागपत में 19 दिन बाद खुलासा

दो युवकों की हत्या करके महंत ने मंदिर में दफनाया

तमसा संकेत, एजेंसी

बागपत। यूपी के बागपत में दो दोस्तों की महंत ने हत्या कर दी। दोनों के शव मंदिर परिसर में ही दफना दिए। किसी को शक न हो, इसलिए ऊपर से टाइल्स (सीमेंटेड ईंट) लगवा दीं। 19 दिन बाद इसका खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने गुरुवार तड़के 3 बजे दोनों के शव बरामद किए।

पुलिस पहुंचने से पहले ही मंदिर का महंत भाग गया था। उसके शिष्यों ने गुनाह कबूल किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढा खोदा तो दोस्तों अंकित (25) और इसरार (32) के सड़े हुए शव मिले। अंकित दिव्यांग था। कपड़े-घड़ी से दोनों की पहचान हुई। पुलिस ने महंत के दोनों शिष्यों को हिरासत में ले

लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अंकित की बहन का महंत से अफेयर था। अंकित अपने दोस्त इसरार को लेकर 25 जुलाई को उसे समझाने गया था। वहां विवाद बढ़ा तो महंत ने दोनों की हत्या कर दी और अपने शिष्यों के साथ दोनों के शव मंदिर के पीछे दफना दिए। मामला जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर चांदीनगर थाना क्षेत्र के सिगोली तगा गांव का है। पुलिस ने कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन और गांव के लोगों से पूछताछ की तो लहचौड़ा स्थित गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि दोनों आखिरी बार गणेश मंदिर के आसपास देखे गए थे। पुलिस को महंत और अंकित की बहन के बीच अफेयर की भी जानकारी मिली।

अंकित की बहन से महंत का अफेयर, समझाने-धमकाने गए थे

इसरार के भाई फरीद ने बताया- अंकित की बहन का महंत नरेश नाथ से अफेयर था। दोनों कई बार उसे समझा चुके थे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। 25 जुलाई को भी दोनों महंत को समझाने और धमकाने के इरादे से मंदिर गए होंगे। वहीं उनकी हत्या कर दी गई। गुरुवार तड़के पुलिस ने फोन करके इसरार की हत्या की जानकारी दी। इसके बाद शव की शिनाख्त करवाई गई।

एक घर का इकलौता बेटा, दूसरा 3 बच्चों का पिता था

सिगोली तगा गांव में अंकित मां और 5 बहनों के साथ रहता था। वह घर का इकलौता बेटा था। दो बहनों की शादी हो चुकी है। अंकित अविवाहित और बेरोजगार था। अंकित के घर के ठीक सामने इसरार का मकान है। इसरार मजदूरी करके परिवार चलाता था। उसके परिवार में पत्नी फिरदौस और तीन बच्चे हैं। बेटी इसरा 6 साल की है, जबकि बेटे आयान की उम्र 5 साल और फैजान की उम्र 3 साल है।

इसरार के पिता रिड़कू ने बताया- मेरा बेटा और अंकित 25 जुलाई की दोपहर बाइक से निकले थे। जब अगले दिन तक दोनों नहीं लौटे तो हमने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोनों के फोन पर कॉल की तो मोबाइल नहीं उठा। 27 जुलाई की शाम से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 29 जुलाई को हमने चांदीनगर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया।

सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पुस्तकों और समाचार पत्रों को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा : डीएम

मेधावी छात्राओं को सम्मान

तमसा संकेत, संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी) जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुजीबपुर तथा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, देवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही शैक्षिक, आवासीय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास परिसर, कक्षाओं सहित विद्यालय के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की स्थिति परखी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 15 मेधावी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा राज्य स्तरीय कुरास प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विभिन्न कक्षाओं में पहुंचे और अध्ययनरत छात्राओं से उनकी पढ़ाई के संबंध में बातचीत की। उन्होंने छात्राओं से विषयों, पढ़ाई के तरीके और विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के बारे में जानकारी ली।

छात्राओं से कक्षा में लिया पढ़ाई का फीडबैक

डीएम ने स्मार्ट बोर्ड का संचालन छात्राओं से स्वयं करवाकर देखा और डिजिटल माध्यमों से हो रहे शिक्षण की स्थिति का भी जायजा लिया।उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ तकनीकी दक्षता भी आवश्यक है, इसलिए कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक एवं ज्ञानवर्धक उपयोग किया जाना चाहिए।

12 छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करने वाली कक्षा सात की छात्रा रागिनी को जिलाधिकारी ने विशेष रूप से सम्मानित किया। छात्राओं से संवाद के दौरान एक छात्रा ने जिलाधिकारी से पूछा कि आईएएस बनने के लिए किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। इस पर डीएम ने कहा कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपने आसपास की छोटी-छोटी गतिविधियों पर ध्यान दें और हर चीज को समझने की जिज्ञासा अपने अंदर विकसित करें।उन्होंने कहा कि स्वच्छता जैसी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।

समाचार पत्र और पुस्तकों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह

जिलाधिकारी ने छात्राओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने तथा पुस्तकों का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों और उनके कारणों की जानकारी रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को कंप्यूटर एवं डिजिटल संसाधनों का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल से दूरी बनाए रखने और अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई तथा ज्ञान अर्जित करने में लगाने पर जोर दिया।

बाराबंकी में सर्पदंश से 6 साल के बच्चे की मौत

परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से किया इनकार

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी के सिरौली-गौसपुर क्षेत्र के अरियामऊ गांव में गुरुवार दोपहर सर्पदंश से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक श्लोक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है।

गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे श्लोक घर के पास शौच के लिए गया था। इसी दौरान एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे इलाज के लिए कजियापुर स्थित एक निजी चिकित्सक के पास ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बालक ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि श्लोक के पिता सूरत में मजदूरी करते हैं, जबकि बालक अपनी मां के साथ गांव में रहता था। इकलौते बेटे की

असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिरौलीगौसपुर के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सरोज, नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय, लेखपाल प्रदीप कुमार वर्मा और बदोसराय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राम अवतार सरोज मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई की।

प्रशासन की ओर से शव का पोस्टमॉर्टम कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया।

योजना : गर्लफ्रेंड से चेहरे पर खून, मुंह पर टेप वाली तस्वीर बनवाई, पिता को भेजकर फिरौती मांगी

11वीं का छात्र पबजी में तीन लाख हारा

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में 11वीं के छात्र ने PUB-G में 3 लाख रुपए हारने के बाद अपने अपहरण की झूठी कहानी रच दी। गर्लफ्रेंड की मदद से AI से ऐसी फोटो बनवाई, जिसमें उसके मुंह पर टेप और शरीर पर खून के निशान दिख रहे थे। फोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है।

छात्र ने पिता को वॉट्सएप पर फोटो भेजी और मैसेज लिखा- 1 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो बेटे की लाश मिलेगी। फोटो देखते ही पिता घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्र का फोन सर्विलांस पर लगाया। करीब 2 घंटे बाद मंगलवार रात 2 बजे उसे दोस्त के घर से पकड़ लिया।

मामला जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर सिकरीगंज का है। 16 साल के छात्र के पिता कपड़ा कारोबारी हैं। उसकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है। सत्यप्रकाश संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11वीं में पढ़ता है। पुलिस के मुताबिक, छात्र को PUB-G खेलने की लत है। गेम खेलने के चक्कर में उसने दोस्तों और कुछ जानने वालों से पैसे उधार ले लिए। धीरे-धीरे उस पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो उसने अपहरण की योजना बनाई। उसने दिल्ली में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और ऐसी फोटो बनाने को कहा, जिसमें लगे कि उसका अपहरण हो गया है। गर्लफ्रेंड ने AI की मदद से उसकी फोटो तैयार की।

सर्विलांस से खुला राज, दोस्त के घर मिला छात्र

एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया- पुलिस ने छात्र के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। जांच में पता चला कि छात्र का फोन सिकरीगंज में है। इसके बाद पुलिस ने सिकरीगंज पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। रात करीब 2 बजे पुलिस टीम वहां पहुंची तो छात्र अपने दोस्त के घर आराम करते मिला। पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। पूछताछ में सामने आया कि छात्र ने कर्ज चुकाने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी।

मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाला, वाईफ़ाई से कनेक्ट कर फोटो भेजी

प्लान के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे छात्र घर से सिकरीगंज जाने की बात कहकर निकला। वहां पहुंचने के बाद उसने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। बाद में फोन को एक दोस्त के Wi-Fi से कनेक्ट किया। रात 9:47 बजे छात्र ने पिता के वॉट्सएप पर AI से बनाई गई फोटो और धमकी भरा मैसेज भेजा। लिखा- तुम्हारा लड़का मेरे पास है। तुम लोग अपने बेटे को सही-सलामत देखना चाहते हो तो जैसा बोल रहा हूं, वैसा करो। तुम्हें अपने बेटे की फिक्र नहीं है क्या? जल्द एक लाख रुपए भेजो, नहीं तो लाश मिलेगी।

बाराबंकी में विरासत और विकास यात्रा प्रगति पर

बौद्ध-धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सूचना आयुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा की

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी । बाराबंकी में विरासत के संरक्षण के साथ विकास की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। यह बात राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने रामनगर स्थित निरीक्षण गृह में कही। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए।

डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि जिले में विरासत को सम्मान देने के साथ विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। तीर्थ स्थलों का विकास केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय परंपराओं के संरक्षण से भी जुड़ा है। प्रदेश सरकार इसी सोच के साथ धार्मिक और

ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

यात्रा के दौरान उन्होंने रामनगर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने भगवान लोधेश्वर महादेव मंदिर के प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर का भी उल्लेख किया। कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव मंदिर का विकास होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बाराबंकी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बाराबंकी को करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात मिली है। प्रदेश सरकार बाराबंकी को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित कर रही है।

कलेक्ट्रेट से शिव बाबा धाम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा स्केटिंग करते बच्चों ने की अगुवाई

तिरंगे की शान, देश की पहचान

शिव बाबा धाम पहुंचने के बाद तिरंगा यात्रा का समापन तिरंगा कंसर्ट के साथ हुआ। यहां मौजूद लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। इसके बाद 1000 मीटर लंबे तिरंगे के साथ कार्यक्रम का समापन किया

यात्रा

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अंबेडकरनगर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को अंबेडकरनगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश लेकर निकली यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, युवाओं और आम लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। जिलाधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रंजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह, प्रशिक्षु आईएएस थनिगईयरसन टी,जिला विकास अधिकारी सविता सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा की अगुवाई स्केटिंग कर रहे बच्चों ने की।

सामूहिक गायन के दौरान बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौजूद रहे। तिरंगे के साथ आयोजित कार्यक्रम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता और देशप्रेम का संदेश दिया।

कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शिव बाबा धाम पहुंची यात्रा

तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर शिव बाबा धाम पहुंची। रास्ते में तिरंगा हाथों में लेकर शामिल लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। यात्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ युवाओं तथा आम नागरिकों की भी भागीदारी रही। तिरंगे के साथ आगे बढ़ते प्रतिभागियों से पूरा मार्ग देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा।

तिरंगा देश की एकता और गौरव का प्रतीक : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों को राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों के लिए जागरूक करना है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के त्याग और बलिदान की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने 'हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा' का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की बात कही।

सरयू के तेवर पड़े नरम, तीसरे दिन भी घटा जलस्तर कटान ने बढ़ाई चिंता

अंबेडकरनगर में नौ सेंटीमीटर नीचे आया नदी का पानी

- खतरे के निशान से 1.20 मीटर नीचे पहुंचा जलस्तर

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को नदी का जलस्तर नौ सेंटीमीटर घटकर 84.36 मीटर पर पहुंच गया। नदी का खतरे का निशान 85.56 मीटर है। ऐसे में सरयू का पानी खतरे के निशान से 1.20 मीटर नीचे है। जलस्तर में लगातार गिरावट से बाढ़ की आशंका के बीच स्थानीय लोगों और किसानों को राहत मिली है। आराजी क्षेत्र में बंधे की ओर बढ़ रहा नदी का पानी अब स्थिर हो गया है। इससे बाढ़ की आशंका को लेकर चिंतित ग्रामीणों को राहत मिली है। हालांकि जलस्तर घटने के बाद भी मांझा क्षेत्र में कटान का खतरा बरकरार है। नदी किनारे कटान प्रशासन और बाढ़ विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है।

इटौरा ढोलीपुर गांव के पूरब सरयू कई स्थानों पर कटान कर रही है। कटान को रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड अयोध्या की ओर से ट्री स्पर और बंबू क्रेट लगाए जा रहे हैं। विभाग की ओर से संवेदनशील स्थानों पर बचाव कार्य जारी है।

इसके बावजूद कुछ स्थानों पर नदी का कटान थम नहीं रहा है। ग्रामीणों को खेतों और आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उनका कहना है कि कटान पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में नुकसान बढ़ सकता है।

सरयू का जलस्तर लगातार नीचे आने के बावजूद प्रशासन और बाढ़ विभाग ने निगरानी कम नहीं की है। नदी के किनारे और संवेदनशील स्थानों पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। संबंधित विभाग की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं।

अधिकारियों की निगरानी खास तौर पर उन क्षेत्रों में है, जहां नदी का कटान जारी है। जलस्तर में दोबारा बढ़ोतरी या कटान की स्थिति में तत्काल बचाव कार्य शुरू करने के लिए विभाग सतर्क है। फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे होने से बाढ़ का तत्काल खतरा कम हुआ है, लेकिन कटान प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनी हुई है।

फास्ट न्यूज

गर्मी ने बढ़ाई मुश्किल, स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्रा हुई बेहोश

अंबेडकरनगर। गुरुवार को कटेहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बैजपुर में गर्मी के कारण एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पढ़ाई के दौरान छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रा के अचानक बेहोश होने से विद्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बताया गया कि छात्रा कक्षा में मौजूद थी। इसी दौरान गर्मी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। घटना के बाद विद्यालय में मौजूद शिक्षकों ने छात्रा को संभाला।

किसानों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

अंबेडकरनगर। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन में किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कृषि, श्रमिकों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में सभी फसलों के लिए सी2+50 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई।

तिरंगे के रंग में रंगा कटेहरी, रैली निकाल दिया एकता-अखंडता का संदेश

कटेहरी (अंबेडकरनगर)। 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत गुरुवार को कटेहरी ब्लॉक स्थित देव इंद्रावती महाविद्यालय में तिरंगा रैली निकाली गई। भारत सरकार और अवध विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के निर्देशों के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, युवाओं, स्वयंसेवकों और नागरिकों ने हिस्सा लिया।

नई भाजपा जिला टीम पर अपने ही खेमे से सवाल

हिमांशी सिंह की पोस्ट से मचा सियासी घमासान

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। भाजपा की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद संगठन के भीतर की नाराजगी अब सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। पार्टी से जुड़ी महिला नेता हिमांशी सिंह की फेसबुक पोस्ट ने नई कार्यकारिणी को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी है। उन्होंने संगठन में पदों के बंटवारे से लेकर पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका तक पर सवाल खड़े किए हैं।

हिमांशी सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। इसके विपरीत हाल में संगठन से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने पद आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पक्षपात और चाटुकारिता जैसे आरोप भी लगाए हैं।

नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन में जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। अब हिमांशी सिंह की पोस्ट ने इस बहस को खुला राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। उनके सवालों का केंद्र उन कार्यकर्ताओं की भूमिका है, जो लंबे समय से संगठन के लिए काम करते रहे हैं। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर संगठनात्मक फैसलों पर असंतोष जताया है। हालांकि, उन्होंने जिन आरोपों का उल्लेख किया है, उन पर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आयुष अस्पतालों की रफ्तार पर डीएम की नजर हुई समीक्षा

50 शैयायुक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय की प्रगति पर भी चर्चा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिले में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आयुष समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयुष विभाग के चिकित्सालयों की प्रगति और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्माणाधीन अस्पतालों से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक कई बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में निर्माणाधीन आयुष चिकित्सालय भवनों की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रस्तावित चिकित्सालयों के लिए उपलब्ध भूमि की अद्यतन स्थिति भी देखी गई। इसके साथ ही 50 शैयायुक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में आवश्यक तेजी लाने और सभी काम निर्धारित मानकों के साथ तय समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिले के सभी आयुष चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाओं और उनकी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। कितने मरीजों का उपचार हुआ और उन्हें कौन-कौन सी सेवाएं मिल रही हैं, इसकी भी जानकारी ली गई। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित रखने और मरीजों को सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार देने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योगाभ्यास की स्थिति भी सामने रखी गई। योग प्रशिक्षकों और प्रशिक्षिकाओं की ओर से कराई जा रही गतिविधियों की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने आयुष और योग के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष विभाग की योजनाओं और सेवाओं का प्रचार-प्रसार ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ाने को कहा।

आयुष अस्पतालों की रफ्तार पर डीएम की नजर

निर्माण से लेकर दवाओं तक की हुई समीक्षा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिले में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आयुष समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयुष विभाग के चिकित्सालयों की प्रगति और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्माणाधीन अस्पतालों से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक कई बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में निर्माणाधीन आयुष चिकित्सालय भवनों की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रस्तावित चिकित्सालयों के लिए उपलब्ध भूमि की अद्यतन स्थिति भी देखी गई। इसके साथ ही 50 शैयायुक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में आवश्यक तेजी लाने और सभी काम निर्धारित मानकों के साथ तय समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिले के सभी आयुष चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाओं और उनकी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। कितने मरीजों का उपचार हुआ और उन्हें कौन-कौन सी सेवाएं मिल रही हैं, इसकी भी जानकारी ली गई। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित रखने और मरीजों को सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार देने के निर्देश दिए।

भाजपा की नई जिला टीम तैयार

34 चेहरों के साथ 2027 की चुनावी जमीन मजबूत करने की तैयारी

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। भाजपा ने अंबेडकरनगर में नई जिला कार्यसमिति घोषित कर दी है। 34 सदस्यीय टीम में संगठन के अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। जिला संगठन की नई तस्वीर सामने आने के साथ अब निगाह इस बात पर है कि यह टीम 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक कितनी मजबूती देती है।

नई कार्यसमिति में मनोज मिश्रा, डॉ. राना रणधीर सिंह, सुमन पाण्डेय, अमरेन्द्रकान्त सिंह, पंकज वर्मा, विकास मोदनवाल, शुभम अग्रहरी और विवेक मौर्य को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बाबा राम शब्द यादव, विमलेन्द्र प्रताप सिंह 'मोनू' और विनोद कुमार को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। डिजिटल प्रचार के लिए शाश्वत मिश्रा को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। आकाश कुमार और अरुण राजभर सह-संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी की मीडिया गतिविधियों की जिम्मेदारी बाल्मीकि उपाध्याय को जिला मीडिया संयोजक के रूप में दी गई है। अमित सिंह और गिरीश वर्मा मीडिया सह-संयोजक होंगे।

जिला कार्यालय की जिम्मेदारी संतोष सिंह 'बब्लू' को कार्यालय मंत्री के रूप में दी गई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह और निखिल जायसवाल कार्यालय सह-मंत्री बनाए गए हैं। जिला कार्यसमिति की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब 2027 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अहम दौर होगा। भाजपा की नई टीम के सामने अब संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और जनसंपर्क को गति देने की जिम्मेदारी होगी। नई कार्यसमिति में संगठन के अलग-अलग हिस्सों के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। उपाध्यक्ष और महामंत्री से लेकर जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष, आईटी, सोशल मीडिया, मीडिया और कार्यालय तक पूरा ढांचा सामने आ गया है।

संगठन की कमान में आठ जिला मंत्री

जिला संगठन में कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आठ जिला मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इनमें विनय पाण्डेय, शिवपूजन राजभर, आकाश वर्मा, अंजू पाण्डेय, अभिषेक निषाद, अखण्ड प्रताप वर्मा, उमाशंकर शुक्ला और जय सिंह शामिल हैं। वित्तीय व्यवस्था के लिए राजकुमार सेठ को जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सागर संगवानी और रामसूरत वर्मा सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।

नई टीम में संगठन के साथ पार्टी के डिजिटल तंत्र को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। मनीष मिश्रा जिला आईटी संयोजक होंगे, जबकि सुधांशु ओझा और अंकित अग्रहरी सह-संयोजक बनाए गए हैं।

बारिश भी नहीं रोक सकी तिरंगा यात्रा की रफ्तार

अकबरपुर में विवेक मौर्य की अगुवाई में निकली विशाल बाइक रैली

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। भारी बारिश के बावजूद गुरुवार को अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का जोश कम नहीं हुआ। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक और भाजपा नेता विवेक मौर्य के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली निकाली गई। आयोजकों के अनुसार, रैली में 1500 से अधिक बाइक शामिल हुईं। तिरंगा हाथों में लेकर निकले युवाओं ने बारिश के बीच भारत माता की जय, वंदे मातरम् और हर घर तिरंगा के नारे लगाए।

रैली का शुभारंभ डॉ. गणेश कृष्ण जेटली विद्यालय, शहजादपुर से हुआ। यहां से बाइक सवारों का काफिला पटेल नगर की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर तिरंगे लहराते रहे और देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। बारिश के बीच बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रैली का प्रमुख आकर्षण रही।

रैली की कमान विवेक मौर्य ने संभाली। उनके नेतृत्व में युवाओं का काफिला निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ा। तिरंगे से सजे वाहन और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए बाइक सवार रैली में शामिल रहे। रैली के मार्ग में स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने भी तिरंगा लहराकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। कई स्थानों पर देशभक्ति गीत बजते रहे। सड़क किनारे मौजूद लोगों ने तालियों के साथ रैली में शामिल युवाओं का उत्साह बढ़ाया। रैली पटेल नगर पहुंचने के बाद सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही बाइक रैली का समापन हुआ।

इस अवसर पर विवेक मौर्य ने तिरंगे को देश की पहचान, एकता और गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में योगदान देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। युवाओं से शिक्षा, सेवा और एकता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

शिव भक्ति में डूबा जलालपुर, अयोध्या के लिए निकली कांवड़ यात्रा

उसमापुर दरगाह से सुबह आठ बजे रवाना हुए कांवड़िए

तमसा संकेत, संवाददाता

जलालपुर (अंबेडकरनगर)। श्रावण मास के अवसर पर गुरुवार को जलालपुर क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में नजर आया। छत्रपति शिवाजी कांवड़िया मंडल की ओर से सुबह करीब आठ बजे उसमापुर दरगाह से अयोध्या के लिए कांवड़ यात्रा रवाना हुई। कांवड़ियों के साथ श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़े।

कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की कमान मंडल के अध्यक्ष अंकुश के साथ सुजीत और आकाश ने संभाली। यात्रा शुरू होने के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। भक्ति गीतों और जयकारों के बीच कांवड़िए अयोध्या की ओर रवाना हुए। कांवड़ यात्रा से पहले नगपुर में शिव जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अवधी स्टार पंचम परदेशी ने अपनी गायकी से शिव भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति पर मौजूद श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। जागरण में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम की व्यवस्था विकास निषाद, राजेश गौड़ और अनुराग गौड़ ने संभाली। आयोजन के दौरान शिव भजनों की प्रस्तुतियां चलती रहीं और श्रद्धालु देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगपुर में शिव जागरण के आयोजन के बाद श्रावण मास की कांवड़ यात्रा का क्रम आगे बढ़ा। उसमापुर दरगाह से निकली यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के बीच अयोध्या की राह पकड़ी। कांवड़ यात्रा और शिव जागरण के आयोजन से क्षेत्र में दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा।

चर्चा : रजनीश सिंह के नाम पर सियासी हलचल, 2027 से पहले फैसले के मायने तलाश रहे कार्यकर्ता

भाजपा की नई जिला टीम में बड़ा उलटफेर

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। भाजपा की नई जिला कार्यसमिति सामने आते ही संगठन के भीतर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह नाम है डा. रजनीश सिंह का। पिछली जिला कमेटी में उपाध्यक्ष रहे रजनीश सिंह को नई कार्यसमिति में जगह नहीं मिली है। खास बात यह है कि सदस्यता अभियान में अंबेडकरनगर में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वह नई टीम का हिस्सा नहीं हैं। बुधवार देर शाम नई जिला कार्यसमिति की घोषणा के बाद से ही पार्टी के अंदर इस फैसले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल यह है कि संगठन के सदस्यता अभियान में जिले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नेता को नई टीम में जगह क्यों नहीं मिली? पार्टी की ओर से इस फैसले के पीछे कोई विशेष कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए फिलहाल अलग-अलग स्तर पर इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

रजनीश सिंह का नाम जलालपुर विधानसभा सीट की भाजपा की राजनीति में भी चर्चा में रहा है। उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों में माना जाता रहा है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के दौर में जिला संगठन की नई टीम से बाहर होना उनके लिए राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है।

हालांकि, सिर्फ जिला कार्यसमिति में जगह न मिलने के आधार पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

सदस्यता अभियान में नंबर-1, संगठन की नई पारी में नाम गायब

रजनीश सिंह पिछली जिला कार्यसमिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सदस्यता अभियान के दौरान भी उनकी सक्रियता सामने आई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंबेडकरनगर में सदस्यता अभियान में वह पहले स्थान पर रहे थे। अवध क्षेत्र में भी उनका प्रदर्शन दूसरे स्थान का रहा।

इसी प्रदर्शन के बाद नई जिला कार्यसमिति को लेकर उनके नाम पर नजर थी। संगठन में जिम्मेदारी बढ़ने की संभावनाओं की चर्चा भी थी। लेकिन नई सूची आई तो तस्वीर बदल गई। पिछली टीम के उपाध्यक्ष रहे रजनीश सिंह को नई कार्यसमिति में स्थान नहीं मिला।

> **भाजपा ने नई जिला कार्यसमिति के जरिए संगठन की अगली पारी के लिए टीम तय कर दी है। अब निगाह इस पर रहेगी कि नई टीम में जगह नहीं पाने वाले रजनीश सिंह की अगली राजनीतिक भूमिका क्या होगी और जलालपुर की चुनावी राजनीति में उनकी सक्रियता किस दिशा में आगे बढ़ती है।**

कलम के साथी अब तिरंगे के साथ सड़क पर उतरेंगे

शहजादपुर से निकलेगी पत्रकारों की बाइक तिरंगा यात्रा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पत्रकारों की ओर से 14 अगस्त को बाइक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित यात्रा के लिए पत्रकार साथियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। यात्रा अकबरपुर के जुड़वा कस्बे शहजादपुर स्थित गांधी चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर के निकट डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल तक जाएगी।

बाइक तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले पत्रकारों को सुबह 10 बजे शहजादपुर के गांधी चौक पहुंचने को कहा गया है। यहां एकत्रीकरण के बाद सुबह 11 बजे यात्रा रवाना होगी। निर्धारित मार्ग से होते हुए बाइक सवार पत्रकार कलेक्ट्रेट परिसर के निकट स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल तक पहुंचेंगे। आयोजकों ने पत्रकार साथियों से समय से गांधी चौक पहुंचने का अनुरोध किया है, ताकि यात्रा निर्धारित समय पर शुरू हो सके। प्रेस क्लब अंबेडकरनगर के उपाध्यक्ष बृजेंद्र वीर सिंह और ज्ञान प्रकाश पाठक ने पत्रकार साथियों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ी है। इसी क्रम में राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित बाइक तिरंगा यात्रा में पत्रकारों की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी।

सम्पादकीय

जेपीसी में एफसीआरए

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए में संशोधन वाले विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने से पक्ष-विपक्ष के बीच सहमति बनने के आसार कम ही हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसे वापस लेने की मांग पर अड़े थे। इस कानून में संशोधन पर विपक्ष के साथ अमेरिकी सांसद को भी आपत्ति थी। इसके अतिरिक्त ईसाई संगठन भी इस कानून में संशोधन-परिवर्तन के खिलाफ थे।

उचित यही होता कि सरकार इस विधेयक पर संसद में चर्चा कराने को प्राथमिकता देती और फिर आवश्यक समझती तो उसे जेपीसी को भेजती। बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को जेपीसी भेजने से ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी दबाव में आ गई। जो भी हो, किसी कानून में संशोधन सरकार का अधिकार है। विपक्ष प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी आपत्ति जता सकता है, लेकिन वह इस पर अड़ नहीं सकता कि संशोधन किया ही न जाए। आखिर इसके पहले भी एफसीआरए में संशोधन किया गया है और यह इसलिए किया गया था कि कुछ गैर-सरकारी संगठन विदेशी धन के बल पर पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकास विरोधी हरकतें करते हुए पाए गए थे। एफसीआरए यह तय करता है कि एनजीओ, ट्रस्ट आदि विदेश से प्राप्त दान किन उद्देश्यों पर खर्च कर रहा है। एफसीआरए यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक शांति के विरुद्ध न होने पाए। हालांकि एफसीआरए में यह प्रविधान है कि राजनीतिक दल, नेता, उम्मीदवार, जज, सरकारी कर्मचारी आदि विदेशी चंदा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई संस्थाएं यह स्पष्ट करने से इन्कार करती हैं कि उन्होंने विदेश से मिले पैसे किस मद में खर्च किए? ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं कि दान जिस उद्देश्य से लिया गया, उसे खर्च किसी अन्य मकसद के लिए किया गया। इससे भी चिंताजनक यह है कि विदेशी धन पाने वाली कई संस्थाएं राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करती हुई पाई गई हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुडनकुलम परमाणु परियोजना के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने वाले संगठन ऐसा ही करते पाए गए थे? यह निष्कर्ष उस संप्रग सरकार का था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। क्या यह विडंबना नहीं कि आज यही कांग्रेस एफसीआरए में संशोधन के खिलाफ है? देश में कार्यरत एनजीओ एक तरह का उद्यम बन गए हैं।

कई एनजीओ संदिग्ध चरित्र वाले हैं और उन पर देश हित विरोधी कार्यों और खासकर विकास विरोधी माहौल बनाने तथा मतांतरण में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए एफसीआरए में उपयुक्त संशोधन किए ही जाने चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि संप्रभु देश को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि विदेशी धन का दुरुपयोग न होने पाए।

> विधेयक में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी प्रावधान यह भी है कि धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को बनाए रखना अनिवार्य होगा। नामित प्राधिकरण किसी ऐसे स्थल को दूसरे उद्देश्य में बदल या उसकी धार्मिक प्रकृति समाप्त नहीं कर सकेगा।

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति-जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतांत्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 1976 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्रावधान अधिक कठोर होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएस के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहां, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं है। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में 'नामित प्राधिकरण' की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियां स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिक्री से प्राप्त राशि और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने का प्रस्ताव है। भारत में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशी वित्तपोषण के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं अथवा राष्ट्रीय हित से टकराने वाली गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए एफसीआरए का मूल उद्देश्य-विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतंत्र विरोधी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए। यही इस विधेयक की असली परीक्षा है। यदि किसी संस्था ने विदेशी धन का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण, राजनीतिक अस्थिरता अथवा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रहित में ऐसी कठोरता आवश्यक है। मगर दूसरी ओर यदि कोई संस्था अस्पताल चला रही है, गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही है अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचा रही है, तो केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण उसके वर्षों के सामाजिक कार्य और विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर तत्काल सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाना चिंता का विषय बन सकता है। यही कारण है कि जेपीसी के पास जाना इस विधेयक के लिए एक सकारात्मक अवसर है। संसद में बहुमत से कानून पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिन कानूनों का प्रभाव हजारों संस्थाओं, लाखों लाभार्थियों और देश के व्यापक नागरिक समाज पर पड़ता हो, उनकी बारीकी से जांच लोकतंत्र को मजबूत करती है। जेपीसी में विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है, सरकार अपने तर्क स्पष्ट कर सकती है और विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, वित्तीय विशेषज्ञों तथा सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवों को भी सामने लाया जा सकता है।

इसके अलावा प्रभावित संस्था को 90 दिनों के भीतर पुनरीक्षण का अधिकार और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का प्रावधान दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि पंजीकरण बहाल होने पर अस्थायी रूप से निहित संपत्तियां और अप्रयुक्त धन वापस किए जाएंगे। ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह रहेगा कि इन अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता और प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीनीकरण से जुड़ा है। 2026 के नियमों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये विदेशी अंशदान के उपयोग को सक्रिय संस्था की पहचान के रूप में रखा गया है। साथ ही गतिविधि और राज्य-विशिष्ट पंजीकरण तथा अधिक विस्तृत उपयोग संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था निष्क्रिय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जेपीसी को यह भी देखना होगा कि क्या हर छोटी लेकिन वास्तविक सामाजिक संस्था के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना व्यावहारिक मानदंड है। सामाजिक उपयोगिता का मूल्य केवल धनराशि से नहीं किया जा सकता।

एफसीआरए की बहस को केवल 'सरकार बनाम विपक्ष' या 'राष्ट्रवाद बनाम नागरिक स्वतंत्रता' के द्वंद्व में सीमित करना भी उचित नहीं होगा।

ललित गर्ग

भारत सरकार ने...

अशोक भाटिया

अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का सच और सरकार की त्वरित कार्रवाई

आज की दुनिया में सीमा की रक्षा केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं होती, बल्कि यह हाइब्रिड वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुकी है। चीन इस रणनीति का पुराना खिलाड़ी है, जहां वह बिना एक भी गोली चलाए, भ्रामक सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए अपने विरोधी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश करता है।

अरुणाचल प्रदेश भारत का वह सुदूर पूर्वी मुकुट है, जिसकी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व हमेशा से देश की सुरक्षा नीति के केंद्र में रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों से उठी चीनी सेना की 'धीमी घुसपैठ' की खबरों ने एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श को गरमा दिया है। एक ऐसे दौर में जब सीमा पर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, घुसपैठ की ऐसी खबरें न केवल रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी असमंजस पैदा करती हैं। हालांकि, इस बार सरकार और भारतीय सेना ने न केवल इन दावों को पूरी तरह से निराधार और अफवाह करार दिया, बल्कि असाधारण सक्रियता दिखाते हुए स्थिति को तुरंत स्पष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा और उससे जुड़ी सूचनाओं के प्रति कितनी सजग और एक्शन मोड में है। अख़बारों और मुख्यधारा के विमर्श के लिए यह केवल एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का गंभीर विश्लेषण करने का अवसर है कि आधुनिक दौर में सीमा सुरक्षा केवल अग्रिम चौकियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरों की जड़ें 'पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल' की एक तथाकथित फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में खोजी जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों और शिकारियों के पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इस दावे को हवा तब मिली जब सोशल मीडिया पर कुछ धुंधले और असत्यापित वीडियो प्रसारित होने लगे, जिनमें चीनी बुनियादी ढांचे और सैनिकों की उपस्थिति का दावा किया गया था। इस प्रकार की सूचनाएं जैसे ही सार्वजनिक पटल पर आईं, वैसे ही भारतीय सेना के शीर्ष कमान और देश के नीति-नियंताओं ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि सीमा पर भारत ने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है। ऊपरी सुबनसिरी के दुर्गम इलाकों में स्थित सभी अग्रिम चौकियां पूरी तरह से भारतीय बलों के नियंत्रण में हैं। सेना ने स्पष्ट किया कि जिसे 'घुसपैठ' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह असल में चीन द्वारा अपनी सीमा के भीतर किया जा रहा बुनियादी ढांचा विकास हो सकता है, जिसे जानबूझकर भारतीय क्षेत्र के भीतर दिखाकर सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया। सरकार का यह त्वरित और पारदर्शी रुख सराहनीय है, क्योंकि अक्सर सीमावर्ती मुद्दों पर आधिकारिक सूचनाओं में देरी अफवाहों को खाद-पानी देने का काम करती है। इस विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत और चीन के बीच हालिया कूटनीतिक और भौगोलिक घटनाक्रमों पर नजर डालना जरूरी है। भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश की 27 प्रमुख जगहों के नाम पूरी तरह से भारतीय पहचान के अनुरूप दर्ज किए थे। यह कदम चीन के उस पुराने पैंतरे का सीधा जवाब था, जिसके तहत वह अरुणाचल के विभिन्न स्थानों का बार-बार 'पुनः नामकरण' कर उन्हें अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताने की कोशिश करता रहा है। भारत के इस संप्रभु अधिकार और कड़े रुख से बीजिंग निश्चित रूप से असहज हुआ था। विदेश मंत्रालय ने इस मोर्चे पर हमेशा की तरह यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा; चीन की किसी भी कृत्रिम नामावली या काल्पनिक दावों से यह ऐतिहासिक और जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। इसलिए, जब भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली हो, तब देश के भीतर से ही सीमा सुरक्षा पर इस तरह के असत्यापित और कमज़ोर दावे उठना पूरी रक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

किसी भी राज्य...

मो0 इकबाल खाँ

शादी विवाह अनुदान योजना से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को मिला आर्थिक सहारा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंतव्य है कि समाज के हर व्यक्ति का शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास समान रूप से हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों में अनेक योजनाओं का संचालन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से चलायी जा रही सभी योजनाएं केवल वित्तीय सहायता देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक जीवन, बेहतर शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश का पिछडा वर्ग कल्याण विभाग इस संकल्प को धरातल पर उतारने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

किसी भी राज्य या राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक कि समाज का अंतिम व्यक्ति और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विकास की मुख्यधारा से न जुड़ जाए। उत्तर प्रदेश, जो अपनी विशाल आबादी और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, वर्तमान में समावेशी विकास (प्दबसनेपअम ळतवूजी) के एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के उत्थान के लिए योजनाबद्ध और पारदर्शी ढंग से शादी/विवाह योजना लागू की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 210 करोड़ रूपये बजट का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत योजना का वार्षिक लक्ष्य 1,05,000 को लाभान्वित करना है, जिसके सापेक्ष अब तक 64,584 आवेदन प्राप्त हुऐ हैं, जिसमें 5,032 लाभार्थियों को 10.064 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025-26 में 1,16,000 गरीब परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु सम्बन्धितों के खाते में 232 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं में विवाह अनुदान योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को प्रति विवाह रु0 20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय रु0 1,00,000 से अधिक नहीं है। विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र का विवरण देना होता है। योजना में निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया गया है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य

उबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखला को पार कर,नदी स्वयं अपनी मंजिल का पथ तय करती है। स्वस्थ तन,मन और भावनात्मक सोच से ही जीवन की नैया भव चक्र के पार उतरती है।पर यह सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं है की हंसते ,मुस्कराते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें । इसीलिए हमे कदम-कदम पर पथ दृष्टा, कर्मो के निर्जण और संकल्प की जरूरत पड़ती है। हमारा तन ही तो जीवन का मूल स्थूल स्तम्भ है । हमको इसलिए इसकी सुस्वस्थता पर सात्विक दम्भ होना चाहिए । हमको स्वस्थ रहते स्वास्थ्य की कीमत समझ में नहीं आती हैं । इसकी असली कीमत हम गफलत में जब इसे खो देते है तब जानी जाती हैं । हवा, पानी, व्यायाम आदि- आदि के अतिरिक्त, स्वास्थ्य का मुख्य और सीधा पोषक खाद्य है। हम स्वास्थ्य स्वाद के पीछे अखाद्य खा-खा कर बिगाड़ लेते हैं । हमारे बेचारे पेट को तो कोई स्वाद नहीं चाहिए। यह तो हमारे बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद के लालच में शरीर को नाना बीमारियों का प्रसाद देती रहती है। अतः अपेक्षित है कि हम स्वास्थ्य के मूल पोषक सात्विक एवं पौष्टिक आहार पर ध्यान दें । वह हम साथ ही समय-समय पर उदर एवं पाचन क्रिया के विश्राम पर देखें । अब मन में यह प्रश्न आ सकता हैं कि क्या वास्तव में स्वास्थ्य धन हैं? अंग्रेजी में कहावत है HEALTH IS WEALTH क्या सच में यह सही है ? देखने में तो यह आ रहा है कि धन के पीछे अन्धी दौड़ में हम लोग स्वास्थ्य-धन की एकदम अनदेखी करते जरा भी नहीं सकुचाते हैं। और मज़े की बात है इस लापरवाही का स्वास्थ्य पर साक्षात विपरीत प्रभाव का भान ही नहीं कर पाते हैं। मैं तब सोचता हूं क्या स्वास्थ्य ही धन है । यह बता कर चले जाने वाले इसके सही अर्थ से अनजान थे ? या समझदार से समझदार भी आज इसकी अनदेखी करने वाले स्वास्थ्य शब्द का ही अर्थ नहीं जानना चाहते? Health is wealth , पहला सुख निरोगी काया, धन से दवा खरीद सकते है स्वास्थ्य नहीं मिलता हैं । यह तो सच्चाई है।

> प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

वर्तमान में भारत में ...

दुर्गेश्वर राय

भारत समेत दुनिया भर में अदृश्य संबल से आर्थिक क्रांति तक पहुँचा केयरगिविंग

सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य एक-दूसरे पर आश्रित रहा है। जीवन के शुरुआती दौर में शिशु की सुरक्षा से लेकर वृद्धावस्था में जर्जर शरीर को संबल देने तक, देखभाल का मानवीय स्वभाव ही समाज की निरंतरता का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। परंतु सदियों तक स्नेह, त्याग और नैतिक उत्तरदायित्व के आवरण में लिपटा यह कार्य आधुनिक अर्थशास्त्र की मुख्यधारा से बाहर ही रहा। केयरगिविंग यानी देखभालकर्ताओं की यह संकल्पना मूल रूप से मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और स्त्रीवादी अर्थशास्त्र के संगम से उपजी है। औद्योगिक क्रांति के बाद जब काम का विभाजन घर और बाहर की सीमाओं में हुआ तो उत्पादक कार्य केवल उसे माना गया जिसके बदले सीधे तौर पर धन का लेन-देन होता था। इसके विपरीत, घर की चारदीवारी के भीतर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों की देखभाल को प्राकृतिक दायित्व मानकर आर्थिक गणनाओं से बाहर कर दिया गया। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और परिवार का पारंपरिक ढांचा बदला, तब अर्थशास्त्रियों ने यह पहचानना शुरू किया कि यदि घर में देखभाल का अदृश्य आधार न हो तो मुख्य धारा का कोई भी उत्पादक कार्य संभव ही नहीं हो सकता। यहीं से केयर इकॉनमी और औपचारिक केयरगिवर्स की संकल्पना को एक पृथक और अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में केयरगिविंग एक गंभीर जनसांख्यिकीय और आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। दुनिया भर में अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ जन्म दर में गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व की जनसंख्या तेजी से बुजुर्ग हो रही है। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे विकसित देश इस समय केयर क्राइसिस यानी देखभाल के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, जहाँ देखभाल करने वालों की भारी कमी हो चुकी है। इस समय वैश्विक स्तर पर अधिकांश देखभाल का बोझ अब भी अवैतनिक केयरगिवर्स, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के कंधों पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया भर में रोजाना लगभग 16 अरब घंटे का अवैतनिक देखभाल कार्य किया जाता है जो यदि किसी न्यूनतम मजदूरी पर आंका जाए तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक के बराबर होगा। इस भारी-भरकम बोझ के कारण करोड़ों महिलाएं औपचारिक रोजगार, उच्च शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, वैतनिक केयरगिवर्स जैसे नर्स, आया, ओल्ड-एज होम वर्कर और होम-केयर अटेंडेंट की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र को अक्सर कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के अभाव, अनौपचारिक कार्य परिस्थितियों और सम्मान की कमी से जोड़कर देखा जाता है। इसी वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत के नीति आयोग द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट रीइमेजिनिंग केयर : स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयरगिवर्स इन विकसित भारत 2047, एक युगांतरकारी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केयरगिविंग को एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक इंजन के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहाँ पारिवारिक संरचनाएं तेजी से संयुक्त से एकल परिवार में बदल रही हैं और महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहाँ यह रिपोर्ट अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट मुख्य रूप से दोहरे दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला, देश के भीतर एक मजबूत, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, और दूसरा, भारत को दुनिया भर के लिए एक प्रशिक्षित और कुशल केयरगिवर्स का वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनाना। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का पहला महत्वपूर्ण पक्ष भारत के भीतर मौजूदा देखभाल प्रणाली का औपचारिक और मानकीकृत ढांचा तैयार करना है। वर्तमान में भारत में केयरगिविंग का अधिकांश क्षेत्र असंगठित और अनियमित है। नीति आयोग ने इसके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय देखभाल नीति और एक एकीकृत राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद के गठन का स्पष्ट प्रस्ताव रखा है। यह परिषद देश में केयरगिवर्स के लिए न्यूनतम मानक तय करेगी, उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी और उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगी। इसके साथ ही, रिपोर्ट में देखभाल करने वालों के व्यावसायिक और मानसिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। चौबीसों घंटे अपनों या मरीजों की सेवा में लगे केयरगिवर्स अक्सर गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव (बर्नआउट) से गुजरते हैं। रिपोर्ट में उनके लिए रेस्पाइट केयर यानी विश्राम देखभाल, परामर्श सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट का दूसरा और बेहद दूरदर्शी पक्ष भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करना है। जहाँ पश्चिमी देश और पूर्वी एशिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएँ बुजुर्ग होती आबादी और श्रमबल की कमी का सामना कर रही हैं, वहीं भारत के पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। नीति आयोग ने पहचाना है कि विश्व भर में आने वाले दशकों में करोड़ों प्रशिक्षित केयरगिवर्स की आवश्यकता होगी। यदि भारत अपने युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भाषा, तकनीकी कौशल, प्राथमिक चिकित्सा, जेरिएट्रिक यानी वृद्धजनों की देखभाल और बाल देखभाल का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करे, तो भारत पूरी दुनिया के लिए केयरगिवर्स का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे न केवल घरेलू स्तर पर लाखों नए और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा प्रेषण के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रसिद्ध 5आर फ्रेमवर्क को भारत के अनुकूल ढालने पर बल देती है। इसमें पहला कदम देखभाल के काम के आर्थिक और सामाजिक मूल्य को पहचानना है।

योगी सरकार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर सभी जिलों में कराएगी स्थापना, लगेंगे 'एक पेड़ मां के नाम'

पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी संदेश देगी 'वंदे मातरम वाटिका'

भागीदारी

- लखनऊ के कुकरैल में भी वाटिका का होगा विस्तार, अशोक चक्र की 24 तीलियों के बाहरी तरफ लगाए जाएंगे अशोक के पौधे
- जनसहभागिता से होगा आयोजन, भारतीय वन सेवा के वर्तमान/पूर्व अधिकारी, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की रहेगी भागीदारी

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार के मार्गदर्शन में वन विभाग विशिष्ट वनों की स्थापना कर रहा है। प्रदेश में बीते दिनों कई विशिष्ट वन स्थापित किए जा चुके हैं। अब 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम् वाटिका स्थापित की जाएगी। यह वाटिका पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी संदेश देगी। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत हर जनपद में 150 पौधों का रोपण किया जाएगा। जनसहभागिता से इस वाटिका को बसाया जाएगा। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडेय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम् वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां अशोक चक्र बनवाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ फेंसिंग भी होगी। इसमें भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त/वर्तमान के अधिकारियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से पौधरोपण कराया जाएगा।

राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत हर जनपद में किया जाएगा 150 पौधों का रोपण

हर जनपद में एक चयनित स्थल पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी जिलों में 'वंदे मातरम् वाटिका' स्थापित की जाएंगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वन विभाग प्रत्येक जनपद में 'वंदे मातरम् वाटिका' विकसित करेगा। इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी, जिससे अभियान स्थायी हरित धरोहर का रूप ले सके।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक पदयात्रा

विस्थापित परिवार साझा करेंगे विभाजन की पीड़ा

तमसा संकेत, संवाददाता

- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पदयात्रा

लखनऊ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार (14 अगस्त) को लखनऊ में जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक प्रस्तावित पदयात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बनेगी, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपार पीड़ा झेली। जारी कार्यक्रम के अनुसार, लोकभवन प्रेक्षाग्रह में विभाजन विभीषिका से प्रभावित विस्थापित परिवारों के सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म के माध्यम से उस दौर की पीड़ा और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल, महापौर लखनऊ सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र कुमा सिंह, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, विधान परिषद सदस्य इंजी. अवनीश कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, विधान विधायक बख्शी का तालाब योगेश शुक्ला, विधायक लखनऊ पूर्व ओपी श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ब्रज बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अर्चना मिश्रा, महानगर अध्यक्ष भाजपा आनंद द्विवेदी, प्रतिनिधि, पंजाबी समाज, प्रतिनिधि, सिख समाज, प्रतिनिधि सिंधी समाज और प्रतिनिधि, बंगाली समाज समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

फास्ट न्यूज

आशियाना में नाले में गिरी कार

मोहनलालगंज । लखनऊ के आशियाना में गुरुवार दोपहर 1 बजे एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 71 साल का चालक, उनका 8 साल का नाती और एक आया सवार थीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम व अग्निशमन विभाग की मदद से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पिता की मौत के बाद शव से लगवाया अंगूठा

लखनऊ । लखनऊ के रहीमाबाद के खड़ौहा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता की मौत के बाद उनके इकलौते बेटे ने जमीन पर कब्जे के लिए शव के अंगूठे का निशान सादे कागज पर लगवा लिया। इस काम में उसने अपने चचेरे भाई की मदद ली। मौके पर मौजूद गांव वालों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब सामने आया है। परिजनों के मुताबिक, खड़ौहा निवासी छत्रपाल (75) और उनकी पत्नी शिवदेवी के साथ उनके बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी का लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि दोनों बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था।

निधि पांडेय बनी लखनऊ की एसडीएम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने 7 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। बलरामपुर की अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति राय को अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। वहीं बांदा के नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

108 आकांक्षात्मक विकासखंडों की रैंकिंग में सैदनगर ने मारी बाजी

तमसा संकेत, संवाददाता

- जुलाई की रैंकिंग में 70.03 अंक के साथ प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान
- प्रयागराज का बहरिया विकासखंड 69.7 अंक प्राप्त कर दूसरे और संभल का असमौली 68.82 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर
- पांच थीम के 50 इंडीकेटर्स के आधार पर विकासखंडों का किया जाता है प्रति माह मूल्यांकन

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना का प्रयास रंग ला रहा है। इसी के तहत प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, सामाजिक विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित 50 इंडीकेटर्स पर काम किया जा रहा है। इन इंडीकेटर्स की प्रगति की नियमित समीक्षा और रैंकिंग के माध्यम से विकासखंडों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिसमें रामपुर जनपद के सैदनगर विकासखंड ने आकांक्षात्मक विकासखंडों की जुलाई-26 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य एवं पोषण को 30 प्रतिशत, शिक्षा को 30 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20 प्रतिशत, आधारभूत अवसंरचना को 15 प्रतिशत तथा सामाजिक विकास को 5 प्रतिशत का भारांक दिया गया है।

योगी सरकार ने गोमती को निर्मल बनाने की कवायद की तेज, सीवेज प्रबंधन का बड़ा एक्शन प्लान तैयार

गोमती में गिर रहे 45 नालों को लेकर अब होगी कार्रवाई

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में नदियों को प्रदूषण को दर करने के लिए जोर-शोर से काम कर ही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। अब इन नालों के जरिए नदी में पहुंच रहे सीवेज का शोधन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग एसटीपी से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। शहर में उत्पन्न सीवेज के शोधन के लिए कुल 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित हैं। इनकी कुल शोधन क्षमता करीब 629.5 एमएलडी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वास्तविक डिस्चार्ज और मौजूदा शोधन क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है। ऐसे में गोमती में सीधे पहुंचने वाले सीवेज को रोकने के साथ ही शोधन क्षमता को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। लखनऊ में गोमती नदी करीब 30 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। नगर निगम के रिकॉर्ड में गोमती में गिरने वाले 33 नालों का उल्लेख था।

गोमती में सीवेज रोकने की तैयारी, 160,150 और 65 एमएलडी फ्लो डायवर्जन की योजना

- नमामि गंगे योजना से बदलेगी गोमती की तस्वीर, नालों की टैपिंग से एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा सीवेज
- गोमती में प्रदूषण रोकने को तैयार हुआ मास्टर प्लान, पीएफआर एनएमसीजी को भेजी गई
- पीपराघाट-घैला में मॉड्यूलर एसटीपी, मरवारा और दौलतगंज प्लांट भी होंगे अपग्रेड

45.56 लाख आबादी, 7.52 लाख घर

वर्ष 2026 में लखनऊ नगर की अनुमानित आबादी करीब 45.56 लाख है। शहर में कुल 110 वार्ड हैं और करीब 7.52 लाख घर हैं। इनमें से लगभग 4.01 लाख यानी 53.32 प्रतिशत घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार और नालों के जरिए गोमती में पहुंच रहे प्रदूषित पानी को रोकना नदी संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में आबादी के सापेक्ष करीब 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज (गंदा और अपशिष्ट जल) उत्पन्न होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज करीब 880.70 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। इसमें 690.33 एमएलडी सीवेज नालों के माध्यम से और 190.71 एमएलडी सीवर नेटवर्क के जरिए प्रवाहित होता है।

धारा-34 के विशेष अभियान में 2.21 लाख से अधिक वाद निस्तारित

योगी सरकार में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को मिली रफ्तार

- लाखों मामलों का हुआ निपटारा
- धारा-80 (भू-उपयोग परिवर्तन) के 49,855 वादों का निस्तारण किया गया
- धारा- 116 कुर्रा-बंट-वारा के वादों का 22,451 निस्तारण किया गया

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित न्याय और जनस-मस्याओं के प्रभावी निस्तारण की नीति के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को लगातार तेज किया जा रहा है। शासन स्तर से की जा रही नियमित मॉनिटरिंग और विशेष अभियानों का असर राजस्व वादों के निस्तारण के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सीमांकन/पैमाइश से संबंधित धारा-24 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 28,556 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 91,472 नए वाद आए, जिनमें से 39,645 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में 80,383 वाद विचाराधीन हैं। पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों की संख्या महज 24 है। धारा-24 के तहत सबसे अधिक विचाराधीन वादों वाले जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी और मथुरा शामिल हैं। नामांतरण/दाखिल-खारिज से संबंधित धारा-34 में भी बड़े स्तर पर निस्तारण किया गया। 31 दिसंबर 2025 तक 48,910 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 14,70,133 वाद आयोजित हुए, जिनमें से 10,96,814 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं, 45 दिन से अधिक अवधि से लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए 15 से 25 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में ही 2,21,667 वादों का निस्तारण किया गया। धारा-80 के तहत भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े मामलों में 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 28,797 वाद आए, जबकि 49,855 वादों का निस्तारण किया गया।

धारा-24, 34 और 80 के वादों के निस्तारण में तेजी

पुराने मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर

योगी सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों में पुराने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि विशेष अभियान, नियमित समीक्षा और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से लंबित वादों के निस्तारण की गति बढ़ी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, आमजन को समयबद्ध न्याय और राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शी एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

अब स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेंगे सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थी

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 5 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें डिजिटल युग की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने 5 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की है। FIRST ORIGIN NextGen Edutech Pvt. Ltd. के सहयोग से CSR के माध्यम से शुरू इस पहल के प्रथम चरण में 5 विद्यालयों में एक-एक स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है।

इसी क्रम में बुधवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में उद्घाटन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव, निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह, उपनिदेशक श्री जे राम और FIRST ORIGIN के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

निदेशक श्री संजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश में 103 सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। पायलट प्रॉजेक्ट के तहत निडोरी (गाजियाबाद), बदनौरा (बुलंदशहर), हस्तिनापुर (मेरठ), बरेली और पीलीभीत में स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए हैं। इनमें स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल, दो एयर कंडीशनर व वुडेन फ्लोरिंग की सुविधा है।

राज्यमंत्री श्री असीम अरुण ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम केवल पढ़ाई का तरीका बदलने की पहल नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास है। तथा प्रशिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाना है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हुए युवाओं को व्यावहारिक एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक और उद्योगपरक बनाने के लिए उद्योगों द्वारा आवश्यक रॉ मैटेरियल UPSDM प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनौती : ईडी-सीबीआई से जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

आय से अधिक संपत्ति का आरोप एससी पहुंचे राहुल

तमसा संकेत, एजेंसी

- राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने इस मामले को लखनऊ बेंच से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। राहुल ने यह याचिका 7 अगस्त को दाखिल की थी।

लखनऊ । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का CBI और ED से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए थे। मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल, कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने CBI और ED से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में CBI विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने 25 अप्रैल को लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें राहुल गांधी की संपत्ति की जांच CBI और ED से कराने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में CBI निदेशक, ED निदेशक, CBDT चेयरमैन, SFIO निदेशक, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग (DoPT) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को पक्षकार बनाया है।

तस्वीर याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की है। इस मामले में CBI ने एस. विग्नेश शिशिर से बुधवार (12 अगस्त) को 7 घंटे और मंगलवार को 6 घंटे पूछताछ की थी।

सीबीआई बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश से 13 घंटे पूछताछ कर चुकी है

एस. विग्नेश शिशिर मंगलवार को CBI के जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे। उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया, जहां करीब 7 घंटे तक सवाल-जवाब का सिलसिला चला। विग्नेश शिशिर के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत और विदेश से जुड़े कथित लेन-देन, विदेश यात्राओं और अन्य आरोपों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए।

कूड़े और बजबजाती नालियां देख प्रभारी मंत्री भड़के

लखनऊ । लखनऊ में गुरुवार को लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया। अयोध्या दास प्रथम, अयोध्या दास द्वितीय, फैजुल्लागंज द्वितीय और गोमतीनगर वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां देखकर मंत्री भड़क गए। इसके बाद नगर आयुक्त द्वारा कार्यदाई संस्था लायन एनवायरो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जोन 4 के जेडएसओ पंकज शुक्ला और एसएफआई रश्मि का पांच दिनों की सैलरी कटौती करने का निर्देश दिया गया है। इनकी शिकायत पहले भी पार्षदों ने की थी। जोन तीन के एक सुपरवाइजर राजेश खन्ना को निलंबित किया गया है। निरीक्षण में सबसे खराब स्थिति फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड में मिली। महीनों से नालियां साफ नहीं हुई थीं। करोड़ों रुपये खर्च के बाद भी जमीनी स्तर पर काम न दिखने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जनता के पैसे से भुगतान लेने के बाद भी एजेंसियां काम नहीं करेंगी तो कठोर कार्रवाई होगी।

यूपीएसडीएम और आईआईए के बीच हुआ एमओयू

युवाओं को मिलेगा इंडस्ट्री का सीधा एक्सपोजर

तमसा संकेत, संवाददाता

- युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार और अप्रेंटिसशिप से सीधे जोड़ा जाएगा।
- प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने पर जोर।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाने तथा उन्हें रोजगार और अप्रेंटिसशिप के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार मौजूद रहे।

इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट लिंकेज को मजबूत करना, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाना, इंडस्ट्री एक्सपोजर उपलब्ध कराना

देवरिया में टीचर गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागे, कईयों का जमीन पर इलाज

तिरंगा यात्रा में 80 छात्राएं बेहोश तबीयत बिगड़ी

अफरा-तफरी

तमसा संकेत, एजेंसी

देवरिया । देवरिया में गुरुवार दोपहर तिरंगा यात्रा में शामिल 80 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल पहुंचते ही कई छात्राएं बेहोश हो गईं। उल्टियां होने लगीं।

आनन–फानन में उन्हें देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक साथ इतनी छात्राओं के अस्पताल पहुंचने से ट्रॉमा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई। बेड कम पड़ गए। कुछ छात्राओं को जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया, जबकि एक-एक बेड पर दो-दो छात्राएं लिटाई गईं।

6 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम छात्राओं के इलाज और निगरानी में जुटी रही। हालत में सुधार होने पर 21 छात्राओं को घर भेज दिया गया, जबकि करीब 59 छात्राएं अभी भी भर्ती हैं। सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालय की 6 से 12वीं क्लास की छात्राएं हैं। डॉक्टरों का कहना है बच्चियों ने कुछ खाया नहीं था। भूखे-प्यासे धूप में खड़े रहने के कारण छात्राएं सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हुई हैं। फिलहाल छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। भाजपा हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। गुरुवार दोपहर 12 बजे पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज से यात्रा शुरू हुई। लेकिन सुबह 9 बजे से ही कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं को बुला लिया गया था। यात्रा में करीब 20 स्कूलों के लगभग 2,500 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी समेत तमाम भाजपा नेता भी शामिल हुए। करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए दोपहर करीब एक बजे रवींद्र शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची।

स्कूल पहुंचते ही बीमार पड़ी छात्राएं

यात्रा पूरी होने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे जैसे ही छात्राएं वापस स्कूल पहुंचीं। कई छात्राएं बेहोश हो गईं तो बाकी को उल्टियां होने लगीं। आनन-फानन में सभी को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने छात्राओं में डिहाइड्रेशन के लक्षण बताए हैं। अस्पताल में भर्ती छात्राओं में रिंकी कनौजिया (18), अंजलि (15), अंकिता (14), पल्लवी (15), छाया (15), शिवानी (14), रितिका (18), रंभा (16), पल्लवी (17) और रीता (18) समेत अन्य शामिल हैं।

> मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एसके मिश्रा ने बताया बच्चियों में डिहाइड्रेशन के लक्षण मिले हैं और सभी की निगरानी की जा रही है। ओआरएस और स्लाइन दिया जा रहा है। 6 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। फिलहाल छात्राओं की हालत खतरे से बाहर है।

एसपी भी छात्राओं का हाल जानने पहुंचे

घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी अभिजीत आर. शंकर भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अधिकारियों ने छात्राओं को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

'यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' के राष्ट्रीय मंच पर छाए कुंवर यशोवर्मन सिंह चंदेल

तमसा संकेत, संवाददाता

महोबा । लखनऊ के सिटी म्यूजियम में आयोजित हुआ YFI का भव्य उद्घाटन संस्करण; अवध की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता के संगम पर हुई परिचर्चा।

महोबा से विशेष रूप से पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यशोवर्मन सिंह चंदेल; कहा– ₹युवाओं में इतिहास और भविष्य की दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता₹।

लखनऊ। म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट (LMHA) में आयोजित 'यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' (YFI) के उद्घाटन संस्करण में देश भर के युवा विचारकों, उद्यमियों, कलाकारों और बौद्धिक वर्ग का बड़ा जमघट देखने को मिला।

कार्यक्रम में अपनी प्रभावी उपस्थिति और विचारों से छाप छोड़ते हुए कुंवर यशोवर्मन सिंह चंदेल ने कहा, ₹मैं विशेष रूप से

इस आयोजन का हिस्सा बनने लखनऊ आया हूँ। यहाँ देश की भावी पीढ़ी के साथ हुई सार्थक परिचर्चा से यह स्पष्ट है कि युवाओं में अपनी समृद्ध विरासत को सहेजने के साथ-साथ भविष्य की सोच को एक नई और सकारात्मक दिशा देने की अद्भुत क्षमता है।₹ चंदेल ने जोर देकर कहा कि बुंदेलखंड और अवध जैसी ऐतिहासिक भूमियों का गौरवशाली इतिहास आज की युवा पीढ़ी के लिए केवल संग्रहालय की शोभा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह 21वीं सदी के भारत के निर्माण का प्रेरणास्रोत बनना चाहिए।

फास्ट न्यूज

रेलवे पार्सल में 42 लाख का माल 2 लाख दिखाया

आगरा । आगरा में रेलवे की पार्सल बोगी से करीब 42 लाख रुपए का माल महज 2 लाख रुपए का दिखाकर दूसरे राज्य भेजने के मामले में बड़ा खेल सामने आया है। विजिलेंस जांच में जीएसटी चोरी के लिए ट्रांसपोर्टर और तीन जीएसटी अधिकारियों की कथित मिलीभगत सामने आई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सोमवार को तीन जीएसटी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

स्टेशन पर छूटा कैमरे से भरा बैग

आगरा । कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP की मुस्तैदी एक बार फिर लोगों के लिए मिसाल बन गई। करीब 10 लाख रुपये कीमत के महंगे कैमरे और गैजेट्स से भरा बैग खो गया था। इससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सूचना पर GRP ने महज 8 घंटे में बैग बरामद कर उसके मालिक को सुरक्षित सौंप दिया।

दिल्ली निवासी संदीप कुमार आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनका कैमरा बैग भीड़ में कहीं छूट गया। बैग में प्रोफेशनल कैमरा, लेंस और अन्य महंगे गैजेट्स रखे थे। सामान की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।

अंशुमान हत्याकांड के फरार आरोपी शंकर पांडेय के घर कुर्की

गाजीपुर । गाजीपुर में बहुचर्चित अंशुमान सिंह हत्याकांड के आरोपी शंकर पांडेय के गौसाबाद स्थित घर पर कोतवाली पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। बुधवार शाम 6 बजे कोर्ट के आदेश पर टीम ने घर में मिले घरेलू सामान की सूची तैयार कर उसे कब्जे में ले लिया। पुलिस ने तीन कमरों के दरवाजे और खिड़कियों के पल्ले भी उखाड़कर कुर्क किए। गुरुवार शाम 4 बजे मामले की जानकारी हुई।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत अभी तक 13 मामलों में हुई सुलह

तमसा संकेत, संवाददाता

महोबा । ''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशांे के अनुक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान मे विभिन्न प्रकृति जैसे वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले. ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारें से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित कर निस्तारण कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत मध्यस्थ अधिवक्ता श्री गिरीश कुमार पटैरिया द्वारा मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा में वादी रामवाई, जालिम सिंह व प्रतिवादी सिद्वगोपाल ने आपसी सहमती से सुलह समझौता किया । वादी प्रतिवादी में मार्ग पर मिट्टी डालने से सम्बन्धित वाद था। यह वाद पिछले 13 वर्षो से वादि रामवाई, जालिम सिंह व प्रतिवादी सिंद्वगोपाल के बीच चल रहा था, जिसमें दोनो पक्षों ने मध्यस्थ अधिवक्ता के सामने भविष्य कभी भी किसी प्रकार का विवाद न करने हेतु लिखित समझौता किया। इस प्रकार से विवाद का निस्तारण हुआ। श्री हरिहर गुप्ता, सिविल जज(सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन कई पक्षों के बीच में मध्यस्थ अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न विवादों में सुलह कराई जा रही है, आगे भी यह अभियान जारी है, जिसमें अभी तक 13 मामलो में सफलता पूर्वक सूलह कराई जा चुकी है।

आज गोरखपुर समेत 15 शहरों में बरसात, सड़कें तालाब बनीं, बाइकें फंसकर बंद

यूपी में मानसून पकड़ेगा जोर

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर/आगरा/मेरठ। यूपी में गुरुवार को मौसम बदल गया। गोरखपुर, आजमगढ़ समेत 15 जिलों में बारिश हुई। जौनपुर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। गोरखपुर में सड़कों पर एक फीट पानी भर गया। कई बाइक फंसकर बंद हो गईं।

लखनऊ में दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं चलने से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। अधिकतम तापमान 32 C और न्यूनतम 27 C रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज 48 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में बरसात की संभावना है। 15 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बिजली भी गिर सकती है।

> वाराणसी बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा-बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके असर से प्रदेश में एक बार फिर मानसून जोर पकड़ेगा। आने वाले दिनों में पूरे यूपी में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

इधर, पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों में 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 49 गांवों में बाढ़ है।

काशी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया है। घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। लोगों को 2 से 3 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कानपुर में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। 5 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। उन्नाव में गंगा का पानी कॉलोनियों में घुस गया है।

गोरखपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बनीं

गोरखपुर में 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही 30-40 KM प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है। वहीं बारिश से सड़कें तालाब बन गईं हैं। कुछ लोगों की स्कूटी और बाइक बंद हो गई। लोग उन्हें खींचकर ले जाते दिखाई दिए। गोरखपुर में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकल आई। इसकी वजह से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. कैलाश पांडेय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम और बारिश में अनियमितता देखने को मिल रही है।

बालिकाओं में लिए अलग स्वच्छ एवं सुरक्षित टॉयलेट, निःशुल्क सैनिटरी पैड की होगी उपलब्धता

स्कूलों में बेटियों को गरिमा के साथ मिलेगी सुविधा

- दो दिवसीय उन्मुखीकरण में 75 जनपदों के कुल 223 प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में किया जा रहा है तैयार
- तीनों मास्टर ट्रेनर अपने जनपदों में सभी विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों को देंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। बेटियों की शिक्षा किसी जैविक प्रक्रिया के कारण बाधित न हो और विद्यालय उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं संवेदनशील

वातावरण का स्थान बने—योगी सरकार इस दिशा में व्यवस्थागत पहल को जमीन तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े विषयों पर शिक्षकों की समझ और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर आयोजित दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद से तीन प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले दिन 13 अगस्त को 37 जनपदों के 111 प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण पूरा हुआ, जबकि शेष जनपदों से आए 112 प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण 14 अगस्त को होगा। इस प्रकार दो दिनों में कुल 223 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य प्रकरण के संदर्भ में विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं और संवेदनशील शैक्षिक वातावरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

> विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर बढ़ेगी समझ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना को विद्यालय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी

प्रशिक्षण में 30 जनवरी 2026 के डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित बताए गए व्यापक पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण सामग्री के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है तथा सुरक्षित और सम्मानजनक मासिक धर्म प्रबंधन उपलब्ध कराने में राज्य और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। साथ ही सरकारी एवं निजी तथा ग्रामीण एवं शहरी सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाओं और यह सुनिश्चित करने पर जोर है कि मासिक धर्म के कारण किसी छात्रा की शिक्षा प्रभावित न हो।

कानपुर में युवती की लाश मिली, हत्या का आरोप

मां बोली- बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर । कानपुर में गुरुवार सुबह 24 साल की गर्भवती युवती का शव आम के बगीचे में मिला। शव के मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर नीला पड़ा था। मां ने प्रेमी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

युवती की मां ने बताया कि बेटी करीब चार महीने पहले प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। करीब एक महीने पहले वह घर लौटी तो बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। इसके पांच दिन बाद वह एक दूसरे युवक के साथ फिर घर से चली गई। इसके 25 दिन बाद गांव के बाहर आम के बाग में उसकी लाश मिली।

मामला घाटमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस ने बताया कि परिजन संदिग्ध युवकों के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए हैं। तहरीर मिलने के बाद एफआईआर

दर्ज की जाएगी। मौत की वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। घाटमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। मां ने बताया कि युवती का शहर में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध था। बेटी उससे आए दिन मिलने जाती थी। घरवाले उसे प्रेमी से मिलने से मना करते थे लेकिन वह नहीं मानती थी। पिता की डांट के बाद वह नाराज रहने लगी थी।

मां के मुताबिक, करीब 4 महीने पहले बेटी बिना बताए प्रेमी के साथ घर से चली गई थी।

पृष्ठ 01 का शेष...

50 हजार रु ...

इसके लिए हर परिवार की एक महिला को चुनाव से पहले 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। वादा था कि रोजगार शुरू करने का बाद सरकार उसका आकलन करेगी। इसके बाद अधिकतम दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए दी जाएगी।

नीतीश सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिलीं। इसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रचंड जीत में जीविका दीदी के खाते में गए 10-10 हजार रुपए का बड़ा योगदान है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- यूपी की धर्मभीरू महिलाएं ये रुपए कभी नहीं लेंगी। भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। उन्होंने दोहराया कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपए देकर योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी।

अखिलेश ने सोशल मीडिया X पर लिखा- "भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20000।" यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं कि जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे। जो लौटा नहीं पा रहीं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने-कचहरी, पुलिस-मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है।

पूर्व डिप्टी सीएम ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुखबीर बादल की सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल को फोन कर सुखबीर का हाल जाना।

सुखबीर बादल पर 4 दिसंबर 2024 को भी हमला हुआ था। गोल्डन टेंपल में सेवादार की धार्मिक सजा भुगतने के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से बात की और सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए।

बादल का सुरक्षाकर्मी संतोष हेगड़े हमलावर को रोकने के प्रयास में घायल हुआ है। हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना से जुड़े CCTV फुटेज और चश्मदीदों से जानकारी जुटाई जा रही है।

महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने बादल की पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बात की। उन्होंने बादल का हाल पूछा। इसके बाद कहा- मैं अभी डीजी महाराष्ट्र को फोन लगा रहा हूं। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी किसी को भी छूटने नहीं दिया जाएगा।

यूपी में सपा सरकार...

राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "इस सरकार ने हर सेक्टर में बहुत लूट-खसोट की है ये सभी भ्रष्ट हैं। ये रिश्वत लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते। तो, हमें उन्हें (भाजपा) हराना है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। फिर कहा कि आजम खान को इस पर पीछे से किसी ने कहा कि रक्षा मंत्री बनाना है तो उन्होंने कहा रक्षा मंत्री बनने से पहले उन्हें राज्य का गृह मंत्री बनाएंगे।"

रामपुर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "हमें उन्हें हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।"आगे शिवपाल ने प्रशासन पर आरोप लगाए और कहा कि आजम खान के साथ जेल में बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा इतने बड़े नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा। आगे कहा, "मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि आजम खान 10 बार विधायक और दो बार सांसद रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम दो बार विधायक रहे हैं, और उनकी पत्नी भी विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। इतने सारे पदों पर रहने, वरिष्ठ नेता और जन-प्रतिनिधि होने के बावजूद, उनके खिलाफ़ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कई आपराधिक आरोप भी शामिल हैं।"

देश में लोगों को ...

उन्होंने दावा किया कि PM मोदी रात में सो नहीं पाते।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कभी चाणक्य और सरदार पटेल जैसे नामों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वह संसद में प्रवेश तक नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में बहुत से लोग कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे हों और डर लगने की बात कहें तो समझ में आती है, लेकिन आज आप उन मसखरों और जोकरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें हमारे दर्शन या इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। यदि किसी दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात होगी तो वह उसकी भी रक्षा करेंगे। रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 12 अगस्त को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में शुरू हुआ था। इसमें सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, अकादमिक जगत, कलाकारों, समुदाय प्रतिनिधियों और नागरिक समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। पहले दिन अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी और असमानता, पर्यावरण, विकास, विस्थापन, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, संस्कृति और शोध जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे।

पीएम मोदी की...

राहुल ने जवाब दिया- मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। उनकी इस बात से लोग हंस पड़े।

उत्तराखंड के चमोली ...

लोगों को 2 से 3 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्नाव मे सड़क पर नाव चलानी पड़ी।

बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से बुधवार को 20 राज्यों में अच्छी बारिश हुई। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है।

देहरादून-मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़क पर आ गिरा। राज्य के 9 जिलों में 67 सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से 204 सड़कें बंद हैं। शिमला के पास शकराला गांव में पहाड़ी लगातार धंस रही है। इससे कई घरों और दीवारों में दरारें आ गई हैं। इलाके में रहने वाले परिवारों को अपने घरों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। यह क्षेत्र शकराला-मल्याणा इलाके में आता है।

चमोली में टनल में ...

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि बाहर निकाले गए सात मजदूरों में से दो को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया है।

संसद सत्र खत्म...

SP सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा किए गए 2.15 लाख दिल्ली के हनुमान मंदिर में दान कर दिए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित भगवान हनुमान के एक प्राचीन मंदिर में चांदी के सिक्कों के राशि दान की। यह राशि पिछले कुछ दिनों में देश भर के सांसदों ने दान की है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र चर्चा की नजर से अच्छा नहीं रहा। पहली बार ऐसा देखा गया है, जब सरकार संसद में चर्चा चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा है।

गुटखा-तंबाकू पर...

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, विभाग ने 10 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें कहा गया है कि यह रोक अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल तक लागू रहेगी. यानी कर्नाटक में इन प्रतिबंधित उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अब मुश्किल बढ़ सकती है.

198 रन पर ऑलआउट, स्टीव स्मिथ की फिफ्टी, हसन महमूद ने लिए 6 विकेट

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टेस्ट स्कोर 198 रन पर ऑलआउट

प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी

बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर ऑलआउट हो गई। यह टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर 217 रन था। यह 2017 में मीरपुर टेस्ट में बना था।

जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 96 रन बनाकर लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। लंच तक टीम ने 74 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के आखिरी चार विकेट भी जल्दी गिर गए।

बांग्लादेश के हसन महमूद 6 विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करते हुए।

बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन को 2-2 विकेट मिले।

ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका हसन महमूद ने दिया। उन्होंने जेक वेदराल्ड को 23 रन पर आउट किया। इसके बाद अगले ही ओवर में ट्रैविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया।

मार्नस लाबुशेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कैमरन ग्रीन 13 रन बना सके। इस तरह लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। दूसरे सेशन में स्मिथ और कैरी ने पारी को संभाला। दोनों ने 55 रन जोड़े, लेकिन कैरी के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी फिर लड़खड़ा गई। ब्यू वेबस्टर 12, पैट कमिंस 9 और मिचेल स्टार्क 1 रन बनाकर आउट हुए।

स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली

ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। स्मिथ ने एलेक्स कैरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। यह ऑस्ट्रेलिया की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। कैरी 19 रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम टेस्ट स्कोर

रैंक	स्कोर	मैदान	तारीख
1	198	डार्विन	13 अगस्त 2026
2	217	मीरपुर	27 अगस्त 2017
3	244	मीरपुर	27 अगस्त 2017
4	269	फतुल्लाह	9 अप्रैल 2006
5	307/7	फतुल्लाह	9 अप्रैल 2006

आकाशदीप-मुकेश की डीएसपी नौकरी पर पांच साल की शर्त

आकाशदीप-मुकेश को 5 साल क्रिकेट खेलना होगा

पटना, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को बिहार पुलिस में DSP बनाए जाने के बाद अब सरकारी सेवा को लेकर नई शर्त सामने आई है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, दोनों क्रिकेटरों को 5 साल का बॉन्ड भरना होगा। इस अवधि में उन्हें सक्रिय क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहना अनिवार्य होगा।

उन्हें विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट में सक्रिय खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेना होगा। यदि वे बॉन्ड में तय शर्तों का पालन नहीं करते हैं या क्रिकेट खेलना पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो उनकी सरकारी सेवा पर असर पड़ सकता है।

बिहार सरकार के 2026 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ़ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन रेगुलेशन के तहत, नियुक्त खिलाड़ियों को नौकरी जॉइन करने की तारीख से पांच साल तक एक्टिव खिलाड़ी के तौर पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा। सरकारी नौकरी में रहते हुए खेलों में अपनी भागीदारी बनाए रखना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई खिलाड़ी तय शर्तों के मुताबिक खेल कॉम्पिटिशन में एक्टिव रूप से हिस्सा नहीं ले पाता है, तो उसकी उसकी सेवा स्थायी किए जाने में समस्या आ सकती है।

बिहार सरकार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा रहा है।

अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 42 रन से हराया 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

अटल-जादरान में 231 रन की साझेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी

अफगानिस्तान ने बुधवार को बेलफास्ट में आयरलैंड पर 42 रन की जीत दर्ज की। टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का आखिरी मैच 15 अगस्त को बेलफास्ट में ही खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 343 रन बनाए। सेदिकुल्लाह अटल ने 143 और इब्राहिम जादरान ने 107 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड 48 ओवर में 301 रन पर ऑलआउट हो गई। एंडी बालबर्नी ने 109 और कर्टिस कैम्फर ने 84 रन बनाए। अफगानिस्तान से यमीन अहमदजई ने 4 विकेट और राशिद खान ने 3 विकेट लिए। आयरलैंड के मैकडोनफ ने 3 और गेविन होई ने 2 विकेट चटकाए। अटल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अफगानिस्तान को शुरुआत में ही झटका लगा। पिछले मैच के टॉप

स्कोरर रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे ओवर में आउट हो गए। इसके बाद अटल और जादरान ने दूसरे विकेट के लिए 231 रन की साझेदारी करके पारी संभाली। यह वनडे में अफगानिस्तान के लिए इस विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है।

दोनों ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड करीन सादिक और मोहम्मद शहजाद के नाम था, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 218 रन की साझेदारी की थी। अटल ने अपने 25वें जन्मदिन पर शतक लगाया। उन्होंने पारी के बीच के ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी की और जब भी पारी धीमी पड़ने लगी, खासकर स्पिन के खिलाफ बाउंड्री लगाकर फिर से गति बढ़ाई। अटल ने लगातार बाउंड्री लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वे 150 रन के करीब पहुंचते दिख रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर गलत टाइमिंग वाले शॉर्ट पर आउट हो गए।

जादरान ने भी अटल का पूरा साथ दिया। उन्होंने वनडे करियर का 7वां शतक लगाया। जादरान की पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा।

बड़े लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड ने धीमी शुरुआत की। शुरुआती पहले 8 ओवर में टीम केवल 25 रन बना सकी।

10 हार के बाद भी गंभीर के समर्थन में मिश्रा

कहा-कोच के साथ खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, रेड-बॉल क्रिकेट को देना होगा समय

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के लिए अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। टेस्ट में 10 हार के बाद भी पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने उनका समर्थन किया है। मिश्रा ने कहा कि इस दौर के लिए सिर्फ कोच को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को भी ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और गंभीर को रेड-बॉल क्रिकेट में समय मिलना चाहिए। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया ने शानदार नतीजे दिए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं। इसी वजह से टीम के कोचिंग सेटअप और खासतौर पर गंभीर की भूमिका पर चर्चा होती रही है।

गंभीर के कार्यकाल में न्यूजीलैंड ने भारत को घरेलू मैदान पर 3-0 से हराया, जबकि साउथ अफ्रीका

के खिलाफ भारत को घर में 2-0 की हार झेलनी पड़ी।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से गंवाई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भी भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है। ऐसे में आने वाली टेस्ट सीरीज टीम के लिए बेहद अहम होने वाली हैं।

मिश्रा का मानना है कि गंभीर को टेस्ट क्रिकेट में अपनी योजनाएं लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट में समय दीजिए। उन्हें टीम के नए खिलाड़ियों को समझाने की जरूरत है। कोच और खिलाड़ी की भूमिका का फर्क बताते हुए मिश्रा ने कहा, कोच का काम मानसिक पहलुओं और स्किल्स पर काम करना है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान पर प्रदर्शन करना होता है। उन्होंने कहा, आपको दबाव लेना होता है, परिस्थितियों को समझना होता है। आपको समय बिताना होता है और परिस्थिति, खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट के अनुसार अपना खेल बदलना होता है।

> **अपनी बात समझाने के लिए मिश्रा ने राहुल द्रविड़ का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, राहुल द्रविड़ को खुद को स्थापित करने में 1-1.5 साल लगे थे। उसके बाद प्रदर्शन में सुधार आया। मिश्रा के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह मिलना ही काफी नहीं है। खिलाड़ियों को हालात के हिसाब से अपना खेल बदलना भी आना चाहिए।**

मिश्रा ने कोच को दोष देने से इनकार किया

लगातार खराब नतीजों के बीच अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग कोच रखने की चर्चा भी सामने आती रही है। मिश्रा इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

मिश्रा ने कहा, कोच के लिए यह मुश्किल है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कई सालों से एक कोच सभी फॉर्मेट के लिए रहा है। किसी भी कोच को समय देना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा, टेस्ट मैचों में हमारे पास कम अनुभव वाले नए खिलाड़ी हैं। कोच और खिलाड़ियों को साथ मिलकर काम करने और विकसित होने में समय लगता है।

मनोरंजन

2007 में रिलीज हुई थी आवारापन श्रिया सरन थीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस

19 साल बाद आवारापन की 'आलिया' का शॉकिंग खुलासा

नई दिल्ली। निर्देशक मोहित सूरी के डायरेक्शन में साल 2007 में अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन को रिलीज किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्री श्रिया सरन ने आलिया का मुख्य किरदार निभाया था। बेशक आज आवारापन एक कल्ट मूवी मानी जाती है, लेकिन उस वक्त ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस बीच आवारापन एक्ट्रेस श्रिया सरन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है कि आवारापन के फ्लॉप होने से उनके साथ इंडस्ट्री में भेदभाव हुआ था।

फिल्म आवारापन फिलहाल अपने सीक्वल को लेकर चर्चा में बनी हुई है, जिसके जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आवारापन 2 (Awarapan 2) से पहले अभिनेत्री श्रिया सरन ने पिंकविला को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और कई राज खोल हैं, उन्होंने बताया है- जब आवारापन बन रही थी तो उस वक्त मैं काफी एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि ये मूवी दर्शकों को काफी पसंद आएगी और हिट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारी मूवी असफल रही। मुझे लगता है कि उस वक्त आवारापन अपने समय से आगे की फिल्म थी। बेशक मूवी को सफलता नहीं मिली, लेकिन ये कई अवॉर्ड शो में नॉमिनेट हुई थी। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई, जब किसी भी अवॉर्ड शो से मुझे न्योता नहीं मिला। एक तरह से मेरे साथ भेदभाव सा हुआ था, जिससे मुझे काफी बुरा लगा था। लेकिन खैर हर किसी के जीवन में ऐसा दौर आता है। अच्छी बात ये है कि अब आवारापन 2 आ रही है और इसको लेकर जो क्रेज दिखाई दे रहा है, वह वाकई आनंद पहुंचा रहा है। इस तरह से श्रिया सरन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। मालूम हो कि आवारापन 2 को शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

> **बात की जाए श्रिया सरन की अपकमिंग मूवी के बारे में तो आने वाले समय वह अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जिसको 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले श्रिया की इस फ्रेंचाइजी की दोनों मूवीज हिट साबित हुई हैं।**

चिरंजीवी को देख इन्फ्लुएंसर पोटी मामा हुए भावुक पैरों में झुककर रोने लगे

चोट के बावजूद भतीजे वरुण ने चिरंजीवी के पैर छुए

नई दिल्ली। फिल्म कोरियन कनकराजू के एक इवेंट में फिल्म के एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पोटी मामा स्टेज पर भावुक होकर रो पड़े।

उन्होंने बताया कि वह कई सालों से अपने आइडल चिरंजीवी से मिलने का सपना देख रहे थे। भावुक होकर वह ऑडियंस में बैठे चिरंजीवी के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर गिर पड़े। चिरंजीवी ने उन्हें तुरंत उठाया और गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने पोटी मामा को अपने पास फ्रंट रो में बैठाया और उनके साथ समय बिताया। चिरंजीवी ने उन्हें एक तस्वीर भी गिफ्ट की।

बता दें कि 11 अगस्त को हैदराबाद में फिल्म की ग्रैंड 'मेगा ब्लॉकबस्टर सक्सेस सेलिब्रेशंस' आयोजित हुई थी। इसमें मेगास्टार चिरंजीवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसी इवेंट से फिल्म के लीड एक्टर और चिरंजीवी के भतीजे वरुण तेज का वीडियो भी सामने आया। इसमें वरुण स्टेज पर अपने चाचा के पैर छूते नजर आए। खास बात यह है कि पैर में चोट के बावजूद वह झुककर चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वीडियो में चिरंजीवी उन्हें संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरुण तेज की यह सादगी और परिवार के प्रति सम्मान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बता दें कि वरुण तेज को हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'भारी' के लिए वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते समय घुटने में चोट लग गई थी। वरुण तेज मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'कोरियन कनकराजू' एक तेलुगु हॉरर-कॉमेडी है। फिल्म का निर्देशन मेरलपाका गांधी ने किया है। इसमें रितिका नायक और सत्या भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 38 करोड़ के बजट वाली फिल्म 'कोरियन कनकराजू' ने 6 दिन में दुनिया भर में 25.54 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

33 साल पहले आया था दूरदर्शन का आईकॉनिक देशभक्ति गीत

नई दिल्ली। देशभक्ति गीत हमेशा से सिनेप्रेमियों की फेवरेट रहे हैं। समय-समय पर हिंदी सिनेमा की तरफ देश प्रेम को जगाने वाले एक से बढ़कर एक सॉन्ग को रिलीज किया गया है। लेकिन ऐसा गाना ऐसा भी है, जो पिछले 33 सालों से स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की भावना जगता आ रहा है। साथ ही ये भारतवासियों में एकता का प्रतीक भी माना जाता है।

इस गाने को सिनेमा जगत के 4 अलग-अलग गायकों ने अपनी आवाज दी थी और इसमें कई फिल्मी सितारे भी मौजूद रहे। खास बात ये थी इस गीत को सीधा राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। 90 का दशक हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के तौर पर याद किया जाता है। बड़े पर्दे पर फिल्मों के अलावा इस दौर में दूरदर्शन एकमात्र मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता था। साल 1993 में दूरदर्शन पर एक ऐसा देशभक्ति गीत रिलीज किया गया था, जिसे आज कालजयी माना जाता है।

अजय देवगन से रिप्लेस होने पर आया अनूप सोनी का रिएक्शन

लोग मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए याद रखेंगे

नई दिल्ली। टीवी का सबसे पॉपुलर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' (Crime Patrol) नए सीजन के साथ टीवी पर लौटने की तैयारी में है, लेकिन इस बार नए होस्ट के साथ। क्राइम पेट्रोल को अब अनूप सोनी (Anup Soni) की जगह अजय देवगन (Ajay Devgn) होस्ट करने वाले हैं।

हाल ही में, क्राइम पेट्रोल (Crime Patrol New Host) के नए होस्ट की अनाउंसमेंट हुई। डेढ़ दशक तक दर्शक जिसकी आवाज में 'सावधान रहें, सतर्क रहें' सुना करते थे, अब वह सुनाई नहीं देगी। अब अजय देवगन दर्शकों को सावधान और सतर्क करेंगे। जब तक मेरे करियर में 'क्राइम पेट्रोल' से भी बड़ा कुछ

नहीं आ जाता, तब तक मैं चाहे कितना भी दूसरा काम क्यों न करूं, लोग मुझे 'क्राइम पेट्रोल' के लिए ही याद रखेंगे। 'क्राइम पेट्रोल' से पहले लोग मुझे 'बालिका वधू' के लिए पहचानते थे, लेकिन जब 'क्राइम पेट्रोल' आया, तो लोग 'बालिका वधू' को भूल गए।

अनूप सोनी ने वैरायटी को दिए इंटरव्यू में अजय देवगन के नए होस्ट बनने पर बात की। उन्होंने कहा, ₹मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे प्रकाश झा की फिल्मों 'गंगाजल' और 'अपहरण' में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मुझे यकीन है कि वह शो में अपना अलग अंदाज और नजरिया लेकर आएंगे। मैं नए सीजन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। बात करें वर्क फ्रंट की तो अनूप सोनी भले ही 'क्राइम पेट्रोल' से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके पास लाइन में एक वेब सीरीज और फिल्म है। वह जल्द ही बड़े पर्दे पर अलग किरदार में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।

रिप्लेस होने पर अनूप सोनी का रिएक्शन

करीब डेढ़ दशक तक क्राइम शो को होस्ट करने वाले अनूप सोनी ने एक हालिया इंटरव्यू में अजय देवगन से रिप्लेस होने पर पहली बार रिएक्शन दिया है। एएनआई के साथ बातचीत में अनूप सोनी ने कहा कि लोग हमेशा उन्हें इस शो के लिए याद रखेंगे।

जापान बोला- ये हमारा हिस्सा ■ 80 साल से 4 द्वीपों को लेकर दोनों में विवाद

पुतिन पहली बार जापान के दावे वाले कुरील आइलैंड पहुंचे

दौरा

■ रूस और जापान में 4 द्वीपों को लेकर विवाद

रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव 2010 में कुरील द्वीपों का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति बने थे।

दिमित्री मेदवेदेव बाद में प्रधानमंत्री बने। तब एक बार फिर से वे अगस्त 2010 में कुरील द्वीप समूह के इतुरुप द्वीप के दौरे पर पहुंचे थे।

मॉस्को/टोक्यो, एजेंसी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली बार जापान के दावे वाले विवादित कुरील द्वीप समूह का दौरा किया। क्रेमलिन ने पुतिन के दौरे का वीडियो जारी किया। उन्होंने कुरील द्वीप पर एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। पुतिन की इस यात्रा के बाद जापान ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह इलाका उसका हिस्सा है। रूस और जापान के बीच प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों को लेकर 80 साल से विवाद है। जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है जबकि रूस इन्हें कुरील आइलैंड ग्रुप का हिस्सा मानता है। रूस और जापान के बीच प्रशांत महासागर में स्थित चार द्वीपों को लेकर विवाद है। जापान इन्हें 'नॉर्दर्न टेरिटरीज' (उत्तरी क्षेत्र) कहता है, जबकि रूस इन्हें कुरील द्वीप समूह का हिस्सा मानता है।द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में 1945 में सोवियत संघ ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यहां रहने वाले करीब 17 हजार जापानी नागरिकों को वहां से हटा दिया गया। कब्जे के बाद सोवियत संघ ने यहां हवाई और नौसैनिक अड्डे बनाए। प्रशांत महासागर में रणनीतिक स्थिति होने की वजह से इन द्वीपों का सैन्य महत्व लगातार बढ़ता गया। आज भी रूस यहां बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक सैन्य उपकरण तैनात रखता है।

■ राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को कुरील आइलैंड के इतुरुप द्वीप पर एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया।

> द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादातर देशों ने आपस में शांति संधि (पीस ट्रीटी) पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कुरील द्वीपों के विवाद की वजह से रूस और जापान आज तक ऐसा नहीं कर सके हैं।

दोनों देशों में नाम लगभग एक जैसे

खास बात यह है कि इन विवादित द्वीपों के नाम दोनों देशों में लगभग एक जैसे हैं। रूस इन्हें कुनाशिर, इतुरुप, शिकोतान और हाबोमाई कहता है, जबकि जापान इन्हें कुनाशिरी, एतोरोफू, शिकोतान और हाबोमाई के नाम से जानता है। इन चारों द्वीपों पर करीब 20 हजार लोग रहते हैं। यहां बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन सोना-चांदी जैसे खनिज और मछलियों के बड़े भंडार होने की वजह से इन द्वीपों की आर्थिक अहमियत काफी ज्यादा है।

■ पुतिन ने कैवियार का स्वाद लिया। यह स्टर्जन मछली के अंडों से बनता है और इसे दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में गिना जाता है।

रूस 2 द्वीप देने का तैयार हुआ, जापान नहीं माना

1956 में सोवियत संघ और जापान के बीच राजनयिक संबंध बहाल होने के बाद विवाद सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। उस समय सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने शांति समझौते के बदले शिकोतान और हाबोमाई द्वीप जापान को लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जापान चार से कम मानने को तैयार नहीं था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस और जापान के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 2010 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इन विवादित द्वीपों का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति बने। इसके बाद रूस ने यहां अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत की, जबकि जापान लगातार अपना दावा दोहराता रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। अब पुतिन का यह दौरा इन विवादित द्वीपों पर रूस के दावे को फिर से मजबूत करने के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है।

फास्ट न्यूज

भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट में देरी

वाशिंगटन। अमेरिका में फॉल एकेडमिक सीजन शुरू होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में भारतीय छात्रों सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए समय पर छात्र-वीजा अपॉइंटमेंट न मिलना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

इस मुद्दे पर अब 30 अमेरिकी सीनेटरों ने विदेश विभाग पर दबाव बनाते हुए F, M और J वीजा के प्रोसेसिंग में हो रही देरी का बना रहा है। इस फैसले ने डेमोक्रेटिक सांसदों और नागरिक अधिकार संगठनों में तीखी आलोचना पैदा कर दी है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने सोमवार को जारी नोटिस में बताया कि आईसीई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और एनफोर्समेंट रिमूवल ऑपरेशंस के अधिकारियों के लिए जनरेटेड लो आउटपुट वोल्टेज एमिटर यानी जीएलओवीई खरीदने जा रहा है।

बटन दबाते ही लगेगा 380 वोल्ट का करंट!

वाशिंगटन। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) अपने अधिकारियों और एजेंटों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले दस्तानों पर 2 करोड़ डॉलर तक खर्च करने की योजना

'ईरान रच रहा हत्या की साजिश'

वॉशिंगटन। पिछले महीने तुर्किए से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुपचुप तरीके अपना विमान बदला था। अब खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने ऐसा तब किया जब इजरायल ने चेतावनी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि एयर फोर्स वन पर ईरानी मिसाइलों से खतरा हो सकता है।

टाटा संस में चंद्रशेखरन की जगह ले सकते हैं नरेंद्रन

चेयरमैन की रेस में टाटा स्टील के एमडी सबसे आगे

नई दिल्ली, एजेंसी

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अचानक इस्तीफे के बाद नए उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने आज 13 अगस्त को एक प्रस्ताव पास कर 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस पद की रेस में टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का नाम सबसे आगे है। नरेंद्रन 1988 से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनका पूरा करियर टाटा स्टील में ही रहा है।

चंद्रशेखरन ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो लेकिन वे फरवरी 2027 तक टाटा संस के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। यानी वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इस वजह से टाटा संस के पास नया प्रमुख को चुनने और उनके स्मूथ ट्रांजैक्शन की योजना बनाने के लिए लगभग 6 महीने का वक्त है। टाटा संस के नियमों के मुताबिक चेयरमैन के चयन के लिए 5 सदस्यों की एक खास कमेटी बनाई जाती है। नामों की स्क्रूटनी के बाद कमेटी उनका इंटरव्यू करती है। फिर टाटा संस बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश की जाती है। मुश्किल दौर में शानदार परफॉर्मेंसः नरेंद्रन ने जब पद संभाला, तब टाटा स्टील भारी कर्ज, वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और महंगे विदेशी अधिग्रहणों से जूझ रही थी। उन्होंने कर्ज कम करने, कैश फ्लो सुधारने और डोमेस्टिक पोजीशन मजबूत करने पर काम किया।

लाल किला धमाका अलकायदा ने कराया

यूएन की रिपोर्ट में दावा, एनआईए की जांच में भी यही निकला था, 11 मौतें हुई थीं

नई दिल्ली, एजेंसी

लाल किले के पास हुए धमाके में अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि AQIS अब छोटे-छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है।

इससे पहले आई UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का हाथ बताया था। यानी इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार दो रिपोर्टों में दो अलग-अलग आतंकी संगठनों

के नाम सामने आए हैं। हालांकि, NIA की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी AQIS से जुड़े थे। UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की यह रिपोर्ट 10 अगस्त को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि AQIS अब बिखरे हुए छोटे आतंकी संगठन की बजाय एक क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। संगठन ने अपना लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब बड़े समूहों के बजाय छोटे-छोटे, अलग-अलग सेल के जरिए काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया है।

रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश में जुटा अलकायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIL/दाएश) लंबे समय से ऐसे जहरीले रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि, अब तक वे इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे हथियार बनाना बेहद मुश्किल काम है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन आतंकी संगठनों से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर अब भी ऐसे जहरीले पदार्थ बनाने के तरीके और जानकारी साझा की जा रही है।

फरवरी में ISIL की अंग्रेजी पत्रिका 'इनवेड' में बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ तैयार करने से जुड़े निर्देश प्रकाशित किए गए थे।

10 नवंबर 2025 की शाम हुआ था धमाका

दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर 2025 की शाम जोरदार धमाका हुआ था। इससे आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। कई दुकानों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। 11 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। शुरुआती जांच में ही जांच एजेंसियों को शक हो गया था कि यह हाई-इंटेंसिटी VBIED अटैक था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी।

पत्रकारों पर तंज के लिए मशहूर थीं, कहा- अच्छी मां बनना चाहती हूं

ट्रम्प की वफादार कैरोलिन लेविट ने नौकरी छोड़ी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाने वाली व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 28 साल की लेविट इस महीने के आखिर में व्हाइट हाउस छोड़ देंगी।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेविट अब अपने परिवार और दो छोटे बच्चों को ज्यादा समय देना चाहती हैं। हालांकि, वह ट्रम्प की बाहरी सलाहकार बनी रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करती रहेंगी।

लेविट 27 साल की उम्र में अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनी थीं। मई में बेटी के जन्म के बाद वह कुछ समय के मातृत्व अवकाश पर गई थीं और कुछ दिन पहले काम पर लौटी थीं। उनका एक दो साल का बेटा भी है।

करीब 20 महीने तक कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भी ट्रम्प की नीतियों, फैसलों या विवादों पर मुश्किल सवाल पूछे जाते, तो उनका जवाब देने की जिम्मेदारी अक्सर लेविट ही संभालती थीं। उन्होंने कई बार ट्रम्प का आक्रामक तरीके से बचाव किया और मीडिया के सवालों का तीखे अंदाज में जवाब दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के साथ उनकी कई बार तीखी नोकझोंक हुई, जो सुर्खियों में रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल पूछने वाले एक रिपोर्टर को 'वामपंथी सोच वाला' और 'पत्रकार के नाम पर कलंक' तक कह दिया था। इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ।

डिलीवरी से ठीक पहले भी ड्यूटी निभाई

अप्रैल 2026 में जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी पर पूरी दुनिया की नजर थी, तब कैरोलिन लेविट ने अपना मातृत्व अवकाश शुरू करने के बजाय खुद कैमरे के सामने आकर ट्रम्प प्रशासन की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद ही वह मातृत्व अवकाश पर गईं।

मई 2026 में बेटी के जन्म के बाद करीब दो महीने छुट्टी पर रहीं, जुलाई में काम पर लौटीं और एक महीने बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

■ लेविट ने दिसंबर 2025 में अपनी गर्भावस्था की घोषणा की थी। तब वह पहली ऐसी व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनीं, जो पद पर रहते हुए गर्भवती बनी थीं।

आसमान में सूर्य-चंद्रमा का अद्भुत मिलन

यूरोप में दिखा सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा

लंदन, एजेंसी

यूके और यूरोप के आसमान में हाल ही में एक ऐतिहासिक खगोलीय नजारा देखा गया, जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले लगभग तीन दशकों में क्षेत्र का सबसे शानदार माना जाने वाला यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण जब अपने चरम पर पहुंचा, तो दिन के उजाले में भी शाम की धुंधलका छा गया।

विशेष रूप से यूके में स्थानीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे के ठीक बाद इस आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे अद्भुत रूप देखने को मिला, जहां चंद्रमा ने सूर्य के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को पूरी तरह ढक लिया था। ग्रहण की पूर्णता का पथ साइबेरिया (रूस) के उत्तरी सिरे से शुरू हुआ, आर्कटिक महासागर से होते हुए प्रारंभिक शाम में आइसलैंड पहुंचा। फिर यह दक्षिण की ओर यूके की तरफ मुड़ा। उत्तरी स्कॉटलैंड में स्थानीय समय के अनुसार करीब 6 बजे और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर करीब 6:20 बजे आंशिक ग्रहण शुरू हुआ। मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड तथा वेल्स के बड़े हिस्से में साफ आसमान ने दर्शकों को लगभग एक घंटे तक चंद्रमा के सूर्य पर गुजरने का अबाधित नजारा दिया। उत्तरी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में बादल छाए रहे, फिर भी देशभर के ऐतिहासिक स्थलों पर भीड़ जुटी।

बढ़ोतरी : 1.33 लाख करोड़ के खर्चे का मांगा हिसाब, अमेरिका ने इस भारी सैन्य आवंटन पर अपनी गहरी चिंता जताई

पाकिस्तान के भारी-भरकम सैन्य बजट में बढ़ोतरी पर यूएस सख्त

वाशिंगटन, एजेंसी

गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.33 लाख करोड़ रुपये घोषित किया है। यह भारी-भरकम राशि पाकिस्तान के कुल 6.38 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट का लगभग 20.84 प्रतिशत हिस्सा है।

अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के बावजूद सेना पर पानी की तरह पैसा बहाने की इस नीति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। विशेष रूप से अमेरिका ने इस भारी सैन्य आवंटन पर अपनी गहरी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान के रक्षा बजट में 41 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में हथियार, गोला-बारूद और नए सैन्य उपकरणों जैसे फिजिकल एसेट्स के लिए 31,480 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 40 फीसदी अधिक है।

■ पाकिस्तान के भारी-भरकम सैन्य बजट में बढ़ोतरी पर अमेरिका सख्त

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। चिंताजनक बात यह है कि आयात किए गए कुल हथियारों में से 80 प्रतिशत आपूर्ति अकेले चीन द्वारा की गई है, जिससे पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है।

पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी विदेश विभाग की फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान के रक्षा खर्चों की निष्पक्षता और जवाबदेही पर कड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य बजट पर न तो पर्याप्त संसदीय समीक्षा होती है और न ही किसी प्रकार की नागरिक निगरानी व्यवस्था उपलब्ध है।

अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने सरकारी कर्ज, सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियों और रक्षा से जुड़े खर्चों की सटीक जानकारी समय पर सार्वजनिक करे।

मुस्लिम नाटो समझौते के तुरंत बाद अमेरिकी चेतावनी

अमेरिका की ओर से आई यह चेतावनी राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। हाल ही में 7 अगस्त को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच एक त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौता हुआ, जिसे मुस्लिम नाटो के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते में नाटो के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर यह प्रावधान शामिल किया गया है कि किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के ठीक पांच दिन बाद अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसने पाकिस्तान के सैन्य इरादों पर निशाना साधा है।

माल्या- एसबीआई विवाद खत्म करें : बॉम्बे हाईकोर्ट

इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा

मुंबई, एजेंसी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और बैंकों के बीच चल रहे कॉमर्शियल विवाद को अब खत्म करने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से जांच की मौजूदा स्थिति और अटैच की गई संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच ने माल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर दोनों पक्ष इस विवाद को खत्म कर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा।

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि लगभग एक दशक से चल रहे इस मामले को अब एक तार्किक अंत यानी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। 70 साल के विजय माल्या ने याचिका दाखिल कर संपत्तियों को बैंकों को सौंपने के आदेश को

अनुचित बताया था।

इस पर कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल विवादों का समाधान अक्सर खुद विवादों के भीतर ही छिपा होता है। पक्षों को आपसी उलझन में रहने की बजाय व्यावहारिक समाधान यानी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। साल 2020 में माल्या ने विशेष प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम को ED द्वारा अटैच की गई उसकी संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

तमसा संकेत
tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड-224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. 64107/96